सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 35, नई दिल्ली । बुधवार, 17 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता।

03 दिल्ली सरकार ने मुफ्त पानी देने का भ्रम पैदा किया... एलजी का अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र
06 स्थिर और मजबूत रुपए की आहट
08 अगले साल दलित जस्टिस बीआर गवई बनेंगे सीजेआई, बोले वजह सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर

“सड़क किनारे अतिक्रमण के ख़तरे: सुरक्षा और व्यवस्था के लिए बढ़ता ख़तरा” : ओमनी फाउंडेशन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सड़क किनारे अतिक्रमण, जिसमें अनधिकृत संरचनाएं, स्टॉल या सड़कों के किनारे मलबा शामिल है, शहरी योजनाकारों और सुरक्षा अधिवक्ताओं के लिए एक गंभीर चिंता के रूप में उभरा है। हानिरहित प्रतीत होते हुए भी, ये अतिक्रमण कई खतरों को जन्म देते हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और परिवहन नेटवर्क के सुचारू कामकाज को बाधित करते हैं।

सड़कों के किनारे अतिक्रमण कई खतरे पैदा करता है, जिसमें यातायात के प्रवाह में बाधा डालने से लेकर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करना शामिल है। यहां एक लेख है जिसमें इसके खतरनाक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है और यह पता लगाया गया है कि नोडल एजेंसियां इसे संबोधित करने के लिए संघर्ष क्यों करती हैं:

खतरनाक प्रभाव:

यातायात की भीड़: अतिक्रमण से सड़कें संकरी हो जाती हैं, जिससे वाहन यातायात का सुचारू प्रवाह बाधित होता है। इस भीड़भाड़ के कारण न केवल निराशाजनक देरी होती है बल्कि ड्राइवरों के प्रतिबंधित स्थानों से गुजरने पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

पैदल यात्रियों के लिए खतरा: अतिक्रमण के कब्जे वाले फुटपाथ पैदल यात्रियों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उन्हें वाहनों से टकराने का खतरा रहता है। इसके अलावा, अस्थायी संरचनाएं दृश्यता में बाधा डालती हैं, जिससे ड्राइवरों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए खतरों का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

बिगड़ा हुआ आपातकालीन प्रतिक्रिया: एम्बुलेंस, अग्निशमन ट्रक और पुलिस वाहन आपात स्थिति के दौरान अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने के लिए निर्बाध पहुंच पर भरोसा करते हैं।

सड़क किनारे अतिक्रमण इस महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया में बाधा डालते हैं, संभावित रूप से जीवन और संपत्ति से समझौता करते हैं।

पर्यावरणीय गिरावट: अतिक्रमण अक्सर अपशिष्ट और प्रदूषक उत्पन्न करते हैं, जो आस-पास के जल निकायों और मिट्टी को दूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनियंत्रित अतिक्रमण शहरी सौंदर्यशास्त्र और हरित स्थानों के क्षरण में योगदान देता है, जिससे निवासियों के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है।

नोडल एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

कानूनी जटिलता: सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने में संपत्ति के अधिकार, ज़ोनिंग नियम और नौकरशाही प्रक्रियाओं सहित कानूनी बाधाओं की भूलभुलैया से निपटना शामिल है। आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में देरी से अतिक्रमण को समय पर हटाने में बाधा आती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप: कई मामलों में, अतिक्रमणों को मौन या स्पष्ट राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे उन्हें हटाना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। नोडल एजेंसियों को प्रभावशाली हितधारकों के विरोध या प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, जिससे प्रवर्तन प्रयासों में बाधा आ सकती है।

संसाधन की कमी: सड़क किनारे अतिक्रमण को संबोधित करने का काम करने वाली नोडल एजेंसियां अक्सर सीमित मानव और वित्तीय संसाधनों से जूझती हैं। अपर्याप्त जनशक्ति और धन प्रवर्तन अभियानों की प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं, जिससे अतिक्रमण अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है।

सार्वजनिक जागरूकता की कमी: सड़क किनारे अतिक्रमण से उत्पन्न खतरों के बारे में सार्वजनिक उदासीनता या अज्ञानता प्रवर्तन पहल के लिए समर्थन जुटाने के प्रयासों को कमजोर करती है। अतिक्रमण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में समुदाय को शिक्षित करना जमीनी स्तर पर वकालत और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

डॉ अंकुर शरण
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ

अवकाश वाले दिन होगी सरकारी स्कूल के वाहनो की जांच

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा में कार्य दिवसों के अलावा अप्रैल में अवकाश के दिनों में भी स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। नियमों पर खरा पाए जाने पर बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाले वाहनों की भी जांच कराएगा। इसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के 22 ब्लॉक के 1838 स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में 35,014 बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं।

परिवहन आयुक्त की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि 17, 20, 21, 27 और 28 अप्रैल को अवकाश के दिनों में भी स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जिले में गठित बोर्ड की ओर से सभी मापदंडों पर खरा पाए जाने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिस जिले में हरियाणा रोडवेज का फोरमैन व एमवीआई उपलब्ध नहीं होगा, वहां पर रोडवेज का वर्क्स-मैनेजर बोर्ड का हिस्सा होगा।

दूसरी ओर, शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है कि प्रदेश के 22 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना 16 जनवरी से लागू है। अधिकारियों से कहा गया है कि वह स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की जांच करें। शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वह एक सप्ताह में शपथ पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट दें। जिन स्कूलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई की जाए। झज्जर के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने बताया कि कई सरकारी स्कूलों में रोडवेज बसें लगी हैं। यदि दूसरे वाहन लगे हैं तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी।

“असामान्य व्यवहार का सामान्यीकरण: सड़क सुरक्षा में एक खतरनाक प्रवृत्ति”

-डॉ अंकुर शरण

यह लेख चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है कि कैसे मामूली उल्लंघन तेजी से सुरक्षा नियमों की व्यापक उपेक्षा में बदल सकता है। यह लेख विभिन्न उदाहरणों पर प्रकाश डालता है, जैसे तेज गति, लापरवाही से गाड़ी चलाना और पैदल चलने वालों को रास्ता न देना, ये सभी सड़कों पर जोखिम भरे व्यवहार को सामान्य बनाने में योगदान करते हैं।

आज की दुनिया में, असामान्य व्यवहार तेजी से सामान्य होता जा रहा है, और यह सड़क सुरक्षा से अधिक कहीं और स्पष्ट नहीं है। इस सामान्यीकरण के परिणाम घातक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उस परिदृश्य को लें जहां एक ड्राइवर लाल बत्ती तोड़ता है। फटकारे जाने के बजाय, यह व्यवहार अक्सर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाता है, जिससे अराजकता और संभावित रूप से घातक दुर्घटनाएँ होती हैं।

इसी तरह, जब लोग सड़क के किनारों पर अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं, तो यह चिंताजनक है कि कितनी जल्दी अन्य लोग इसे नई सामान्य बात मानने लगते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ जाती हैं।

उन ड्राइवरों के मामले पर विचार करें जो गाड़ी चलाते समय अपने फोन का उपयोग करते हैं। अनगिनत चेतावनियों और यहां तक कि इसके खिलाफ कानून के बावजूद, आदत बनी हुई है। इस व्यवहार का सामान्यीकरण न केवल इसमें शामिल लोगों के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि निर्दोष दर्शकों को भी खतरे में डालता है। एक अन्य उदाहरण सीटबेल्ट के उपयोग के प्रति आकस्मिक उपेक्षा का है। इसकी जीवन-रक्षक क्षमता के स्पष्ट प्रमाण के बावजूद, कई लोग अभी भी इसे आवश्यक एहतियात के बजाय असुविधा के रूप में देखते हुए कमर कसने की उपेक्षा करते हैं।

इसके अलावा, प्रवृत्ति खेल में मनोवैज्ञानिक कारकों की पड़ताल करती है, यह बताती है कि कैसे व्यक्ति अक्सर दूसरों को समान व्यवहार में संलग्न देखकर अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं। यह घटना, जिसे सामाजिक प्रमाण के रूप में जाना जाता है, एक खतरनाक चक्र को जन्म दे सकती है जिसमें समाज के भीतर असामान्य व्यवहार तेजी से सामान्य हो जाता है।

यह इस प्रवृत्ति से निपटने में प्रवर्तन और शिक्षा के महत्व पर भी जोर देता है। व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराकर और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, हम सड़कों पर असामान्य व्यवहार को सामान्य करने की दिशा में काम कर सकते हैं।

सड़क सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन की कमी और कार्यान्वयन के बीच व्यवहारिक परिवर्तन स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। उन क्षेत्रों में जहां प्रवर्तन की कमी है, व्यक्तियों को दण्ड से मुक्ति की भावना महसूस हो सकती है, जिससे नियमों और विनियमों की आकस्मिक उपेक्षा हो सकती है।

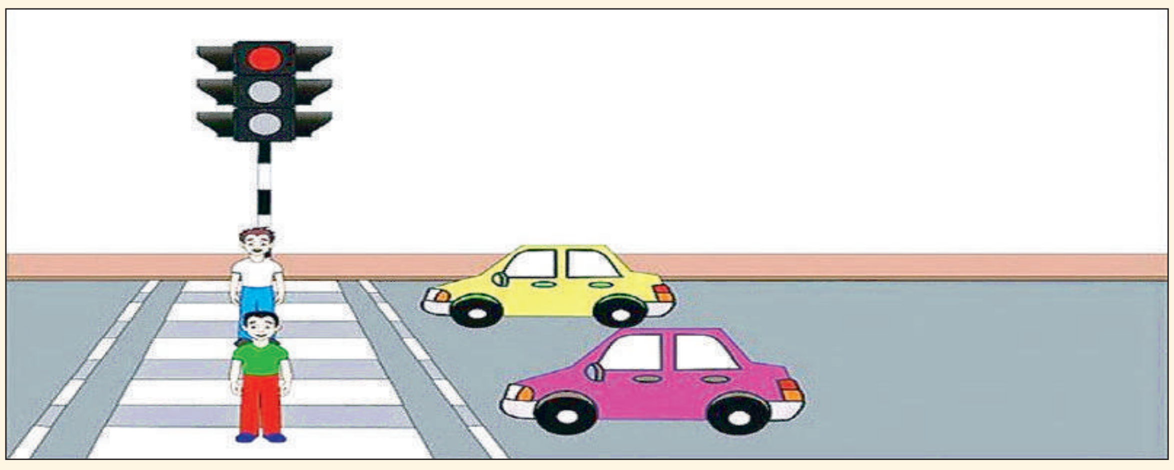

इसके परिणामस्वरूप तेज़ गति से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती चलाना और सीटबेल्ट के उपयोग की उपेक्षा करना जैसी लापरवाही भरी ड्राइविंग हो सकती है, क्योंकि व्यक्तियों को परिणामों का कम जोखिम महसूस होता है। दूसरी ओर, ऐसे वातावरण में जहां प्रवर्तन सख्त है और दंड लगातार लागू होते हैं, व्यक्तियों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। दंड का सामना करने का डर, चाहे जुर्माना, लाइसेंस निलंबन, या कानूनी नतीजों के रूप में हो, जोखिम भरे व्यवहार के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है। नतीजतन, ड्राइवरों द्वारा यातायात कानूनों का पालन करने, सीट बेल्ट पहनने और ध्यान भटका कर गाड़ी चलाने से परहेज करने की अधिक संभावना है। प्रवर्तन द्वारा लाया गया व्यवहारिक परिवर्तन सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत और मजबूत उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करके और गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाकर, अधिकारी अनुपालन और जवाबदेही की संस्कृति विकसित कर सकते हैं, जिससे अंततः दुर्घटनाओं की व्यापकता कम हो सकती है और सड़कों पर लोगों की जान बच सकती है।

असामान्य व्यवहार का सामान्यीकरण सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। लाल बत्ती चलाने से लेकर सीटबेल्ट के उपयोग की उपेक्षा तक, इन मामूली उल्लंघनों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह जरूरी है कि हम सतर्क रहें, जोखिम भरे व्यवहार को सामान्य बनाने को चुनौती दें और अपनी सड़कों पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना बेहद जरूरी है। जब लोगों को नियमों का पालन करने के लिए डर होता है, तो उन्हें नियमों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या कम होती है और सड़कों पर सभी की सुरक्षा होती है।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर फ्लाइओवर से नीचे गिरी, एक युवक की मौत; दो घायल

दिल्ली–गुरुग्राम एक्सप्रेस के झाड़सा फ्लाइओवर पर अनियंत्रित हो गई और फ्लाइओवर से नीचे जा गिरी। इस कार में तीन लोग सवार थे। इनमें से एक युवक की मौत हो गई है। दो अन्य का इलाज जारी है। हालत गंभीर होने के कारण अभी इनके बयान नहीं लिए जा सके हैं। हालांकि यह गुरुग्राम के सेक्टर 15 के बताए जा रहे हैं।

गुरुग्राम। दिल्ली की तरफ से आ रही एक किया कार सोमवार रात दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस के झाड़सा फ्लाइओवर पर अनियंत्रित हो गई और फ्लाइओवर से नीचे जा गिरी। इस कार में तीन लोग सवार थे। तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने इन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया है। इनमें से एक युवक की मौत हो गई है। दो अन्य का इलाज जारी है। बताया जाता है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए फ्लाइओवर पर चढ़ने के दौरान अनियंत्रित हो गई और चार फीट का डिवाइडर फांदकर नीचे जा गिरी। सदर थाना पुलिस ने बताया पुलिस कंट्रोल रूम में कार के फ्लाइओवर से नीचे गिरने की सूचना दी गई थी। इसके बाद जब थाना पुलिस पहुंची तो कार काफी क्षतिग्रस्त मिली। इसमें तीन लोग सवार थे, तीनों को कार से निकालकर अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण अभी इनके बयान नहीं लिए जा सके। हालांकि, यह गुरुग्राम के सेक्टर 15 के बताए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस गुरुग्राम आ रहे थे।

स्मार्ट मोबिलिटी एसोसिएशन की और से दिल्ली परिवहन विभाग को दिल्ली की महिलाओं और जनता को सुरक्षा के प्रति निवेदन, जाने क्या लिखा और क्या किया निवेदन!!!

सरकार की गैर-कार्रवाई के कारण दिल्ली में ऑटो-रिक्शा में यात्रियों की सुरक्षा से समझौता

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में, गंभीर सुरक्षा मुद्दे बढ़े हैं। दिल्ली में जीपीएस/जीपीआरएस के बिना ऑटो रिक्शा चलने के बाद से यात्रा करने से इंकार करना, परमिट धारकों / ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलना जैसी गलत आदतें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और परमिट शर्तों के बावजूद दिल्ली में ऑटो रिक्शा बिना जीपीएस के चल रहे हैं। जीपीएस वास्तविक समय में ऑटो रिक्शा की आवाजाही पर नजर रखने/निगरानी करने के साथ-साथ किसी भी घटना की जांच करने में मदद करता है। कोविड के दौरान, कार्यात्मक जीपीएस डिवाइस की आवश्यकता को विभाग द्वारा सितंबर 2021 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन ऑटो यूनियनों के दबाव के कारण विभाग द्वारा इसे अभी भी बहाल नहीं किया गया है। ऑटो रिक्शा चालक 2010 से प्रत्येक किराया संशोधन में जीपीएस/जीपीआरएस के लिए यात्रियों से 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क ले

रहे हैं। आखिर क्यो ? शर्तों के अनुसार, ऑटो रिक्शा में कार्यात्मक जीपीएस होना आवश्यक है और सरकार फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते समय यह जांचती थी कि जीपीएस कार्यात्मक है या नहीं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इसका पालन नहीं किया जा रहा है। 90% ऑटो रिक्शा में जीपीएस/जीपीआरएस नहीं है या उनके जीपीएस काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नं. काम नहीं कर रहा है, यात्री परमिट धारक द्वारा मना करने, अधिक कीमत वसूलने, दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को जीपीएस चालू हालत में होने पर ही फिटनेस के नवीनीकरण को लागू करके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली की सरकारी जन-परिवहन सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। क्या आप जानते और मानते हैं कि डीटीसी विश्व की सबसे बड़ी विश्वसनीय सार्वजनिक बस सेवा रही है, जो पूर्णतया संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करती है। आज से 10 साल पहले तक डीटीसी दिल्ली के अंदर और आस-पास के प्रदेशों के कई नगरों तक बसें चलाती थी। यह दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से काठमांडू के बीच चलने वाली ऐतिहासिक बस सेवा भी चलाती थी। दिल्ली परिवहन निगम की शुरुआत मई 1948 में की गई थीं। डीटीसी आज की तारीख में एक इंडिपेंडेट कॉरपोरेशन होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अंतर्गत है। इसे दिल्ली की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जोकि किफायती होने के साथ साथ आरामदायक भी है। एक आम आदमी के लिये मेट्रो, ऑटो, टैक्सी इस्तेमाल करना मुश्किल होता है आज महंगाई के दौर में दिल्ली में रहना मुश्किल है। ऐसे में डीटीसी की सेवा नागरिकों के लिये संजीवनी का काम करती है। मगर इस सेवा को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। जिस कारण डीटीसी घाटे से जूझ रही है। डीटीसी बस की सेवा आम नागरिकों को समय पर नही मिल पा रही है कभी कभी घण्टे भर तक बस नही आती जब आती हैं तो एक साथ चार पांच बसे एक ही रूट की आ जाती हैं। दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि दिल्ली की जनता को सुरक्षित, विश्वसनीय सार्वजनिक बस सेवा से वंचित ना करे और डीटीसी को अपनी डीटीसी के नाम की बसे उपलब्ध करवाए। यदि स्टैंड पर कोई बस खड़ी है; तो दूसरी बस उसको पास करके निकल जाती है ड्राइवर कंडक्टर को कोई फर्क नही पड़ता कि स्टैंड पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं जो घाटे का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण हमारे स्कूली बच्चे हैं जबकि उनको देशभक्ति के पाठ पढ़ाये जाते हैं मगर उनको यह नही पढ़ाया जाता कि सरकार को मजबूत करने के लिये हमें सरकारी सेवाओं की फीस अदा करनी चाहिये। हमे डीटीसी की सेवा

लेने के लिये उसकी फीस देनी चाहिये जिससे बहोत से परिवार पलते हैं। मै दिल्ली के सभी छात्रों से निवेदन करना चाहता हुँ की डीटीसी ने करीब 350 रुपये का स्टूडेंट्स पास जारी किया हुआ है जोकि सभी बसों में मान्य है। मेने कई बार बस में सफर के दौरान देखा है जब टिकिट चैक होता है तो बच्चे स्वयं को बहोत अपमानित महसूस करते हैं। इसलिये सभी स्टूडेंट्स को वो पास बनवाना चाहिये जिससे आप अपमानित होने से बचेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान भी देंगे। आइये हम सब मिलकर अपनी दिल्ली की जीवन रेखा को मजबुत करने के लिये आगे आएं और प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद बिना टिकिट यात्रा नही करेंगे। अधिक जानकारी हेतु दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाये।

मेरी दिल्ली मेरी जान मेरा अभिमान। परिवहन विशेष पी डी वर्खिया असिस्टेंट कमिशनर सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड दक्षिणी दिल्ली।

चैत्र नवरात्र-कलश विसर्जन

ज्योतिष मतानुसार कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन करना ही शुभ माना जाता है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानि कि रामनवमी 17 अप्रैल, बुधवार को पड़ेगी और इसी दिन कलश का विसर्जन किया जाना उचित रहेगा।

कलश विसर्जन -:

17 अप्रैल, बुधवार, नवमी तिथि को देवी मां की पूजा-उपासना व कन्या पूजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन कलश विसर्जन दोपहर बाद और सूर्य अस्त से पहले-पहले करना उचित रहेगा।

चैत्र नवरात्रि कलश विसर्जन की विधि-:

चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा और कलश की विधिवत पूजा करें, मां से क्षमा याचना करें, दंडवत प्रणाम करें, उसके बाद ही विसर्जन करना शुभ होता है।

कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिन्दूर लगाना चाहिए।

नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी बड़ी-बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों चीजें रखें। और उनसे आशीर्वाद लें।

आपने जो चुनरी की साड़ी नवरात्र प्रारंभ के समय माता के लिए रखी थी वह चुनरी की साड़ी आप किसी सुहागन स्त्री जैसे नंनद, भुवा व भांजियों को दी जा सकती है। या फिर किसी मंदिर के पंडित को भी दी जा सकती है।

इस नारियल और चुनरी को आप ईशान कोण में रख सकते हैं।

तदुपरांत कुछ समय बाद इस नारियल को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। (ध्यान रहे इस नारियल को किसी अन्य उपयोग में नहीं लेना चाहिए)

इसके बाद कलश में रखे हुए आम-अशोक के पत्तों को हटाएं और कलश के भीतर रखे जल को आम के पत्तों से घर में चारों ओर छिड़कें। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़कें।

जल सबसे पहले पूजा के स्थान में छिड़कें फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़कें। ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए।

बचे हुए जल को घर के पेड़ पौधों में डालें और माता से घर की समृद्धि की कामना करें।

कलश के साथ आपको ज्वारों को भी निकाल लेना चाहिए। एक-एक करके सभी ज्वारे निकाल लें और घर के उन स्थानों पर रखें जहां आप पैसों से जुड़ा कोई सामान रखती हों। कुछ ज्वारे अपने पर्स में जरूर रखें। कलश और बचे हुए जवारे घर के बाहर किसी पेड़ के पास रख दें।

चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन के समय इन मंत्रों का जप कर सकते हैं-:

कलश उठाते समय आपको बाएं हाथ में चावल लेकर ही कलश उठाना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करें।

क्षमा प्रार्थना आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं और यदि आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जप कर सकते हैं-:

कलश उठाने से पहले आपको '

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर॥
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन।

मंत्र का जाप करना चाहिए और

'ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' बोलते हुए कलश उठा लेना चाहिए।।

बड़े बुजुर्गों की सीख राकेश बाटला की जुबानी

सुबह का पानी

सामान्यतः लोग सुबह उठ कर बेड टी के नाम से गरमागरम चाय पीते हैं, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं। आपकी जानकारी हेतु बता दें भारत देश में यह लिवर- अमाशय और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत घातक है। ठंड प्रधान जलवायु वाले यूरोपीय देश में तो उचित हो सकता है लेकिन भारत जैसे गर्म जलवायु के देश के लिए यह सर्वाधिक अहितकर है, लेकिन अज्ञानतावश हम उनकी नकल करने लगे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यूरोप की देन है इस कारण वहां के जलवायु के अनुसार ही उसकी रचना की गई है। भारत देश में सुबह उठते ही शीतल (फ्रिज का नही) जल का सेवन करना चाहिए ये अमाशय को दुरुस्त रखता है, पाचन ठीक रहता है, कब्ज, बदहजमी जैसी शिकायतें नही होती। भारत में यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। आज भी ग्रामीण अंचल में बुजुर्ग इस नियम को अपनाकर स्वस्थ रहते हैं।

बर्ष में दो माह दिसंबर- जनवरी में हल्का गुनगुना (18 से 20 डिग्री) पानी लेना चाहिए।

पति के धन पर पत्नी का कितना हक? कानूनी एंगल से आपको जाननी चाहिए यह जरूरी बात

भारत में घर की महिलाएं आमतौर पर पारंपरिक रूप से वित्तीय मसलों से दूर ही रखी जाती हैं. ऐसे में वे अपने वित्तीय अधिकारों के बारे में नहीं जान पातीं. इस बाबत उन्हें जागरुक करने की आसपास की उनकी दुनिया में न तो जरूरत महसूस की जाती है और न ही वे खुद आवश्यकता महसूस करती हैं कि उन्हें इस बारे में भागदौड़ कर समझ हासिल करनी चाहिए. लेकिन वक्त बदला है. हम जानते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से न सिर्फ आत्मनिर्भर होना जरूरी है बल्कि अपने अधिकारों के बारे में भी जानना जरूरी है. इस दिशा में हमने कानूनी मामलों के जानकारों से बात की और रिसर्च की. आमतौर पर हम महिलाओं के प्रापर्टी में अधिकार के कोण से ही बात करते हैं लेकिन क्या आप जानती हैं कि वित्त से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए. पत्नी होने के नाते आपके क्या कानूनी अधिकार हैं. तलाक या जीवनसाथी की रोग-दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर सबकुछ उथल पुथल हो जाता है, ऐसे में आप जागरूक रहेंगी तो वक्त जरूरत पर हालात को बेहतरी से संभाल पाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसरत वकील और नेशनल कमिशन फॉर वीमन (NCW) की पूर्व सदस्य डॉक्टर चारू वलीखन्ना कहती हैं कि बहुत जरूरी है कि सभी महिलाओं, खासतौर से ऐसी महिलाएं जो कामकाजी नहीं हैं और घर में रहती हैं, को पता होना चाहिए कि आपके पति के क्या क्या फाइेंशनल एसेट हैं. वह बताती हैं कि पति के हर फाइनेंशल अलोकेशन, ऐसेट जैसे कि डीमैट, सेविंग खाते, सेविंग स्कीम व अन्य निवेशों में नॉमिनी के तौर पर आपका नाम हो सकता है. बैंक आदि वित्तीय संस्थान आजकल खाता खोलते समय नॉमिनी भरवाती हैं. इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए. ध्यान दें कि नॉमिनी आप बाई- डिफॉल्ट नहीं होतीं बल्कि इसके लिए फॉर्म में पति को बाकायदा नाम और संबंध मेंशन करना होता है. यह भी हो सकता है कि एसेट मालिक बेटे, बेटी या बहू के नाम को किसी एसेट विशेष में नॉमिनी के तौर पर भरे.

यदि आप ही अधिकतर या सभी एसेट में नॉमिनी हैं तो भी केवल इन फाइनेंशनल एसेट में आपका नाम बतौर नॉमिनी होना ही काफी नहीं है. यदि इस एसेट के ओनर की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो महज नॉमिनी होने के कारण आपको इसका डिफॉल्ट हकदार नहीं मान लिया जाएगा यदि इस एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपये से ज्यादा है. नॉमिनी भर होने से ऐसी सिचुएशन में यह रकम पत्नी के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी. चारू बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, ऐसी विल जो दो गवाहों की मौजूदगी में साइन की गई हो, वह स्वीकार्य होती है. साथ ही, ओनर की रजिस्टर्ड विल (वसीयत) में आपका नाम होना जरूरी है ताकि एसेट आपके नाम पर ट्रांसफर होने में दिक्कत न हो. चारू वसीयत के रजिस्टर होने पर सर्वाधिक जोर देती हैं।

अमेरिका की सुप्रसिद्ध फीमेल इन्वेस्टमेंट गुरु गेराल्डिन वीज़ के निवेश मंत्र जिन्होंने दुनिया हिला दी

गेराल्डिन वीज़ इतिहास की उन शुरुआती और चुनिंदा महान निवेशकों में शामिल हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बतौर स्टॉक गुरु तूती बोलती थी. बतौर महिला निवेशक वीज़ का लंबा सफर दिलचस्प, प्रेरणादायक और तमाम तरह के निवेश मंत्रों से भरा हुआ है. महिला होने के नाते फाइनेंस की दुनिया में उन्हें भी पितृसत्तात्मक भेदभाव का सामना करना पड़ा. वीज़ 1926 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जन्मी थीं. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में न सिर्फ कदम रखा बल्कि किताबों को पढ़कर और तमाम अन्य व्यावहारिक तरीकों के जरिए अपनी समझ विकसित की.

वीज़ को नौकरी नहीं देती थीं कंपनियां!

एक ऐसा भी दौर था जब कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी. तब उन्होंने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट न्यूजलेटर शुरू किया, तब वह 40 की उम्र थीं. मर्द और औरत के भेदभाव के चलते उन्होंने शुरू में इस न्यूजलेटर को G. Weiss के तौर पर अंडरसाइन किया. लंबे समय तक महिला के तौर पर अपनी आइडेंटिटी छुपाई. सत्तर के दशक में उन्होंने खुद को जगजाहिर किया. उनकी वैल्यू-आधारित, डिवेंडेड पर फोकस करने वाली स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटिजी हैरतअंगेज रूप से आउटपरफॉर्म करती थी. 37 साल तक उन्होंने अपना यह सुप्रसिद्ध लेटर जारी रखा.

निवेश करते समय ये ध्यान रखना जरूरी

वीज़ कहती थीं कि ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो डिविडेंड का भुगतान करती हैं, और वह भी नियमित और विश्वसनीय तौर पर. टेलिग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि वीज़ ने अपेक्षाकृत केंद्रित पोर्टफोलियो की भी वकालत की, जिसमें सुझाव दिया गया कि एक निवेशक को 10-20 से अधिक स्टॉक नहीं रखना चाहिए. वीज़ एक वैल्यू निवेशक थीं, लेकिन उनका मानना था कि लोगों को कमाई के बजाय लाभांश (डिविडेंड) पर ध्यान फोकस करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि खातों में लाभ के आंकड़ों में हेरफेर करना बहुत आसान है. (ये जरूर पढ़ें- लड़कियां झिझकें नहीं, निवेश शुरू करें, पैसा डूबेगा नहीं, हाई रिटर्न देंगे ये 3 विकल्प)

वीज़ ने हाई यील्ड वाली और "ब्लू चिप" कंपनियों की तलाश की. ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, साथ ही इनसे उनके लिए अपने लाभांश का भुगतान करना और उन लाभांश को बढ़ाना आसान हो सके. वीज़ ने ऐसे ऐतिहासिक डिविडेंड यील्ड चार्ट बनाए, जब यील्ड ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई तो खरीदारी की और जब यह एकदम निचले स्तर पर पहुंच गई तो बिकवाली की. महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं.

गेराल्डिन वीज़ अपनी किताब और न्यूजलेटर के जरिए निवेशकों को ऐसे सबक देती हैं जो आज भी प्रासांगिक हैं. वह निवेशकों को सात सबक देती हैं, जिनका उनके अनुसार सभी निवेशकों को पाल करना चाहिए. वीज़ ने महसूस किया कि निवेशकों को स्टॉक खरीद से पहले स्टॉक से जुड़े सात क्राइटीरिया पर फोकस करना चाहिए कि इनमें से ज्यादा से ज्यादा या सातों मानदंडो पर स्टॉक खरा उतर रहा हो. पहला, स्टॉक अपने ऐतिहासिक औसत लाभांश यील्ड से अधिक यील्ड दे रहा हो. दूसरा, पिछले 12 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 10 फीसदी की दर से डिविडेंड बढ़ाया होना चाहिए.

वहीं तीसरा है कि नेट एसेट के दोगुने से भी कम वैल्यू पर ट्रेड करना. चौथा है 20 गुना से कम कमाई पर ट्रेडिंग. पांचवा मानदंड है कि उनकी कमाई लाभांश की कम से कम दोगुनी हो. छठा मानदंड है कि कुल मार्केट कैप से 50% कम कर्ज हो. सातवां और आखिरी, वित्तीय रूप से स्थिर हो और ब्लू चिप माने जाने वाले लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के योग्य हो।

गर्मियों में त्वचा की देखभाल कैसे करें? महंगे फेशियल की नहीं पड़ेगी जरूरत, घर में आजमाएं ये टिप्स

गर्मियों में त्वचा की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सर्दियों के बाद अचानक से मौसम बदल जाने का असर त्वचा पर साफ तौर पर देखा जा सकता है. पसीना ज्यादा आने से त्वचा के विटामिंस कम होने लगते हैं और चेहरे की नमी भी खोने लग जाती है. जानिए कुछ टिप्स, जिनसे आप पार्लर में हजारों रुपये खर्च करने के बजाय घर पर ही अपने चेहरे का ख्याल रख सकती हैं.

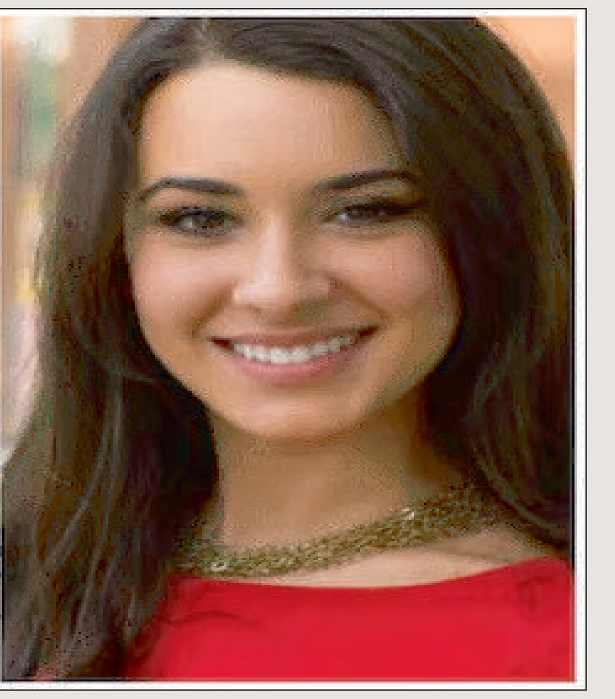

गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही त्वचा का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. अगर आप भी घर और ऑफिस के काम-काज के बीच अपनी त्वचा को ज्यादा समय नहीं दे पा रही हैं तो लॉन्ग टर्म में यह लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है. गर्मियों में घर पर ही कुछ ब्यूटी हैक्स आजमाकर अपनी स्किन की नमी को बनाए रख सकते हैं. इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपको पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

हर्बोलॉजिस्ट और ऑर्गेनिक रिसर्चर डॉ. तेजस्विनी सिंह ने समर स्किन केयर रूटीन शेयर किया है (Summer Skin Care Routine). उन्होंने बहुत आसान हैक्स बताए हैं. इनसे आप न सिर्फ गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, बल्कि एजिंग साइंस को भी कम करने में मदद मिलेगी. सबसे खास बात है कि इस समर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको चेहरे पर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं लगाना होगा. आपके किचन में मौजूद चीजों से ही अपनी स्किन को परफेक्ट ग्लो दे सकते हैं.

गर्मियों में जिस तरह से हम पानी का इनटेक बढ़ा देते हैं, उसी तरह से चेहरे को भी पहले से ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है. त्वचा की नमी कम होने पर न सिर्फ वह रूखी नजर आती है, बल्कि उसका ग्लो भी खत्म होने लग जाता है. गर्मियों में भी स्किन का ग्लो कैसे बरकरार रखें? इसके लिए आपको अपनी स्किन को जरूरत के अनुसार विटामिंस देने होंगे और किचन में मौजूद चीजों से उसका पूरा ख्याल रखना होगा. जानिए गर्मियों में होम रेमेडी से त्वचा की देखभाल कैसे करें.

1- आपका स्किन टाइप चाहे जो भी हो, गर्मियों में अपने चेहरे पर सिर्फ जेल या एक्वा बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें.

2- आप घर पर टोनर बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको गुलाब जल, केसर, ग्लिसरीन, एसेंशियल ऑयल की जरूरत पड़ेगी. सभी चीजों को एक बोतल में डालकर अच्छी तरह से मिला लें. दिन में रोजाना 2-3 बार चेहर पर स्प्रे करें. फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें. बेहतर रहेगा कि आपकी नाइट क्रीम भी जेल बेस्ड हो.

3- अगर त्वचा ज्यादा रूखी है तो बटर बेस और हेवी ऑयल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4- गर्मियों में हफ्ते में 1 बार होममेड फेस पैक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. इससे चेहरे का ग्लो बढ़ेगा और त्वचा तरोताजा भी रहेगी.

5- गर्मियां हैं तो चेहरे पर पसीना आना लाजिमी है. लेकिन उसे फेस पर टिकने न दें. अपने पास टिश्यू या रूमाल रखें और उसे साफ करते रहें. बीच-बीच में रिफ्रेशिंग या हर्बल फेस वॉश से चेहरा धोते रहें.

5- चेहरा धोने के बाद गुलाब टोनर स्प्रे करें. अपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर की मात्रा स्किन की जरूरत और उसके हाइड्रेशन लेवल के अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं.

6- न्यूट्रिशन के लिए आप रोजाना डिटॉक्स वॉटर पी सकते हैं. इसके लिए सौंफ, अजवाइन को पानी में उबालकर पिएं. आप चाहें तो रात में नींबू के छिलकों को 2 लीटर पानी में स्टोर कर सकते हैं. अगले पूरे दिन यही पानी पिएं. इसमें स्किन फ्रेंडली विटामिंस पाए जाते हैं. डिटॉक्स वॉटर से लीवर और ब्लड भी प्योरिफाई होता है.

7- हफ्ते में 2-3 बार फेस स्क्रब का इस्तेमाल करें. उसमें शहद मिला लें. फिर हल्के हाथों से स्क्रबिंग करें. इससे ब्लैकहेड्स को कम करने में मदद मिलेगी.

8- गर्मियों में मेकअप लगाने के बाद भी स्किन डल लगने लगती है. इसलिए रिफ्रेशिंग मेकअप का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. चेहरे पर प्राइमर लगाने के बाद हर्बल मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें.

9- रात में सोने से पहले मेकअप को हटाना बहुत जरूरी है. आप फेस मेकअप को बादाम या नारियल तेल से हटा सकते हैं. उसके बाद हर्बल या फोमिंग फेस वॉश से चेहरा धोएं. फिर चेहरा वाइप करने के बाद गुलाबजल स्प्रे और जेल बेस्ड नाइट क्रीम का इस्तेमाल करें.

10- किसी भी क्रीम में केसर, बादाम या नारियल तेल ऐड करने से उसकी रिचनेस बढ़ जाती है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बादाम के तेल की मात्रा कम रखें. ड्राई स्किन वाले इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं.

अगर आप पार्लर या स्किन विशेषज्ञों के पास जाकर महंगे फेशियल नहीं करवाना चाहते हैं तो घर पर ही 7 से 10 दिनों में क्लीनअप कर सकते हैं. इससे त्वचा तरोताजा रहेगी और उसकी चमक को बरकरार रखा जा सकेगा. इससे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा. जानिए घर पर क्लीनअप कैसे करें-

स्टेप 1- चेहरे को नारियल तेल से साफ करें.

स्टेप 2- चेहर पर आधे घंटे तक शहद लगाकर रखें.

स्टेप 3- हाइड्रेटिंग, फोमिंग हर्बल फेस वॉश से चेहरा धोएं.

स्टेप 4- जेल बेस्ड क्रीम से फेस मसाज करें.

स्टेप 5- अब कुछ देर के लिए होममेड फेस पैक लगा लें.

स्टेप 6- फेस पैक हटाने के बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा लें.

बहुत असरदार है आइस क्यूब मसाज

आपने कई बॉलीवुड/ टीवी एक्ट्रेसेस व ब्यूटी ब्लॉगर्स को आइस क्यूब से मसाज करते हुए देखा होगा. आइस क्यूब यानी बर्फ का टुकड़ा आसानी से मिल सकता है. आइस क्यूब मसाज को बहुत असरदार माना जाता है. इससे त्वचा को रिफ्रेशिंग फील होगा और स्किन टाइट भी होगी. आप चाहें तो ग्रीन टी, तरबूजे के जूस या खीरे से भी आइस क्यूब बना सकते हैं. इसके अलावा खीरे के जूस में शहद, पानी और नींबू का रस मिलाकर भी बर्फ जमा सकते हैं. इससे मसाज करने पर बढ़ती उम्र के निशानों को कम कर सकते हैं.

घर पर फेसपैक कैसे बनाएं?

बाजार से फेसपैक खरीदने के बजाय आप उसे घर पर भी बना सकते हैं. अगर आपकी स्किन ऑयली यानी तैलीय है तो मुल्तानी मिट्टी से फेस पैक बनाएं (Homemade Face Pack for Glowing Skin). स्किन सामान्य है तो उसमें दूध या शहद ऐड कर सकते हैं.

1- बेसन और चावल के आटे से बना फेस पैक स्किन ग्लो बढ़ा सकता है.

2- आप चाहें तो पके चावल को पीस कर भी फेसपैक बना सकते हैं (Rice Skin Care). इसके लिए आपको पके हुए चावल को मिक्सर में ग्राइंड करके उसमें शहद मिलाना होगा. इस फेस पैक को चेहरे पर 1 घंटे तक लगाएं. अच्छी तरह से मसाज करके इसे हटा लें. इसे हर दूसरे दिन या हफ्ते में 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्मियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. यह हाइड्रा फेशियल से बेहतर रहता है।

दिल्ली सरकार ने मुफ्त पानी देने का भ्रम पैदा किया... एलजी का अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल तो फिलहाल तो तिहाड़ जेल में हैं। पूर्वी दिल्ली में फर्श बाजार इलाके में पानी के विवाद में महिला की हत्या का जिक्र किया है। एलजी ने कहा कि घटना के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को आतिशी ने बताकर अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। सीएम केजरीवाल तो फिलहाल तो तिहाड़ जेल में हैं। पूर्वी दिल्ली में फर्श बाजार इलाके में पानी के विवाद में महिला की हत्या का जिक्र किया है। एलजी ने कहा कि घटना के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को आतिशी ने बताकर अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया है, जो दिल्ली में नौ वर्ष से सत्ता में है।

एलजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त पानी का भ्रम पैदा किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं।

सरकरा की विफलता

उनके द्वारा लिखे गए नोट से पृथम दृष्टया स्वीकार होता है कि पिछले 10 वर्षों से अपराध, निष्क्रियता और अक्षमता हो रही है। एलजी ने पत्र में लिखा कि यह यह घटना सिर्फ पहली नहीं है, पानी को लेकर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जो मुख्य रूप से सरकार की विफलता के कारण हुई हैं।

साल दर साल बढ़ी घटनाएं

साल दर साल ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। मीडिया में भी ऐसी खबरें खूब आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या पिछले दशक में और ज्यादा गंभीर हो गई है, गरीब लोगों की बस्तियों में हालात ज्यादा खराब हैं।

दिल्ली विधानसभा में हाल ही आप सरकार द्वारा बजट सत्र में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने सामने आए हैं। पिछले दशक में जल उपचार क्षमता 906 एमजीडी से बढ़ाकर 946 की गई, जो सिर्फ 4.4 प्रतिशत की मामूली बढ़त है। इसी दौरान शहर की जनसंख्या में 15 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है।

जल आपूर्ति में लगभग 290 एमजीडी की कमी है। कुल आपूर्ति का 120 एमजीडी पानी जमीन से निकाला जाता है। मुझे यकीन है कि आप (अरविंद केजरीवाल) जानते हैं कि सोलह रन्नी कुओं में से पांच काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में ट्यूबवेल भी खराब हैं।

आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, टॉप पर है दिल्ली सीएम का नाम; सुनीता केजरीवाल भी पहली बार उतरेंगी मैदान में

परिवहन विशेष न्यूज

आम आदमी पार्टी ने गुजरात लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं जैसी चर्चाएं थीं इसमें सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। इन दोनों के अलावा भगवंत मान मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन संजय सिंह आतिशी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने गुजरात लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं जैसी चर्चाएं थीं, इसमें सुनीता केजरीवाल का भी नाम है।

अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के अलावा पंजाब सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संदीप पाठक, पंकज गुप्ता, संजय सिंह, गोपाल राय, राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, अमन अरोड़ा, गोपाल इटालिया, इसुदान गढ़वी इस लिस्ट में शामिल हैं।

हेमंत खावा, सुधीर वाघानी, अल्पेश कठारिया, राजुभाई सोलंकी, जगमलभाई वाला, ज्वेल वासरा, कैलास गढ़वी, डॉ. रमेश पटेल, मनोज सोराठिया, सागरभाई राबारी, प्रवीन राम, युवराज सिंह जडेजा, राजू करपाड़ा, चेतन रावल, गौरी देसाई, कर्षण भदरका बापू, रेशमाबेन पटेल, नरेश पूनाभाई बरिया, निरंजन वसावा, राधिका राथवा, पंकज पटेल, जयेश संगदा, राम धादुक भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं।

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपनी समस्याओ से अवगत कराने के प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की दिल्ली के टैक्सी बसों के मालिकों को 10 सालो से हो रहीं समस्यायों के समाधान के लिए, और भारत के टैक्सी बस मालिकों/चालकों की सुविधाओं के लिए इन्हे संकल्प पत्र में शामिल करने के लिए('मोदी जी की गारंटी') प्रधानमंत्री मंत्री से मांग करी हैं. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मंत्री क़ो पत्र के माध्यम से बताया की हम दिल्ली के टैक्सी बसों मालिक, लगातार 10 सालो से केंद्र सरकार के मंत्रियो और सांसदों से उपेक्षित रहें हैं इन सब ने इन 10 सालो में ना तो मिलने का सही से समय दिया और हमारी जायज मांगो को इन्होने अनसुना कर दिया.

हमारी मुख्य मांगे थी :-

1:- दिल्ली की आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड लिमिट डिवाइस हटना चाहिए क्योंकि इस स्पीड लिमिट डिवाइस की वजह से एक्सप्रेस वे और हाई वे पर हमारी टूरिस्ट टैक्सी बसें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से ज्यादा नहीं चल सकती जबकि सारी प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हैं. इस से बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना रहती हैं

2:- दिल्ली में पेनिक बटन के नाम पर करोडो रूपया का घोटाला हो रहा हैं और अब इसका नाम बदल कर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस रख कर टैक्सी बसों वाले से 16 हजार रुपये प्रति गाडी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बनाये गए पेनल में प्राइवेट कम्पनी द्वारा लिया जा रहा हैं. जिसमे पेनिक बटन दबाने से कुछ नहीं होता जबकि यह महिलाओ की सुरक्षा के लिए टैक्सी बसों में लगाया जाता हैं, यह एक तरह से मात्र 5 रुपये का प्लास्टिक का बटन हैं जिसकी कीमत हमें 16 हजार से भी ज्यादा देनी पडती हैं. पेनिक बटन के नाम से महिलाओ की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ हो रहा हैं.

3:- कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मेनेजमेंट द्वारा बी एस 3/4 डीजल पेट्रोल की टैक्सी बसों को प्रदूषण की आड़ में हर साल बंद करा कर गरीब टैक्सी बसों के चालक /मालिकों से 20 हजार का जुर्माना वसूल किया जाता रहा हैं. जबकि प्रदूषण के दुसरे कारण जैसे कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी और पराली जलाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते.

4:- इसी तरह प्रदूषण के नाम पर डीजल गाड़ियों को 10 साल में और पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल में स्क्रीप (कूड़ा) बनाया जा रहा हैं. इन गाड़ियों की जब तक फिटनेस सही हैं उन्हें तब तक चलने दिया जाए

5:- डीजल पेट्रोल सी एन जी के दामों में कमी की जाए.

6:- व्यवसायिक टूरिस्ट टैक्सी बसों के खरीदने पर GST कम wकिया जाए.

7:- दिल्ली का MCD टोल टैक्स दिल्ली की सारी व्यवसायिक गाड़ियों से हटवाया जाए.

8:- ड्राइवर के लिए बने नये कानून क़ो जिसमे ड्राइवर क़ो 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना करने का क़ानून केंद्र सरकार ने बनाया था उसे हमेशा के लिए निरस्त करा जाए.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी से विनती करी की दिल्ली नहीं पूरे भारत में करोडो की संख्या में टैक्सी बस मालिक और इनके ड्राइवर्स और इस धंधे से जुड़े लोग हैं आपने अपने संकल्प पत्र में कहीं भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए कुछ नहीं लिखा. इसलिये भारत के टैक्सी बस मालिकों /चालकों और इस धंधे से जुड़े लोगों की मांगो और सुविधायों क़ो अपने संकल्प पत्र में शामिल करें. हमें भी (मोदी की गारंटी चाहिए) आपकी तरफ से कुछ आश्वासन चाहिए क्योंकी इन 10 सालो में ना तो कोई मंत्री हमसे सही से मिले और ना ही किसी मंत्री ने हमारी ऊपर लिखी समस्यायों का समाधान किया. हम इस बारे में एक बार आपसे मिलना चाहते हैं. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से विनती करी और अपने एक प्रतिनिधिमण्डल के मिलने का समय भी माँगा।।

निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, अभिभावकों पर महंगी किताबें और यूनिफार्म खरीदने का दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई

शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों को राहत दी है। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी कि अगर अभिभावकों पर महंगी किताबें और यूनिफार्म स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया तो कार्रवाई होगी। अभिभावकों की शिकायतों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को परिपत्र जारी किया है। साथ ही कहा कि सभी स्कूलों को निदेशालय के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

दिल्ली। नया शैक्षणिक सत्र शुरु होने के साथ ही निजी स्कूलों की महंगी किताबें और यूनिफार्म को स्कूल से ही खरीदने के अभिभावकों की शिकायतों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को परिपत्र जारी किया है।

निदेशालय ने महंगी किताबों और यूनिफार्म की शिकायतों को लेकर दैनिक जागरण की खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर स्कूल किताब और यूनिफार्म को लेकर शिक्षा निदेशालय के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनपर सख्त कार्रवाई होगी।

अभिभावकों को इस संबंध में करें जागरूक

निदेशालय ने निर्देश जारी किए कि स्कूलों को इस सत्र में पेश की जाने वाली पुस्तकों और लेखन सामग्री की कक्षावार सूची व यूनिफार्म नियम के अनुसार पहले से ही स्कूल की वेबसाइट पर और स्कूल में एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा, ताकि अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक किया जा सके।

उंगली पर मतदान की स्याही दिखाएं, दिल्ली में होटल-रेस्तरां और कमरों पर मिलेगा डिस्काउंट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली नगर निगम और होटल व लाजिंग हाउस एसोसिएशन ने 20 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। निगम के करोल बाग और नजफगढ़ जोन के तहत आने वाले होटल व रेस्तरां में यह सुविधा होगी।निगम के साथ मिलकर लाजिग हाउस व होटल व रेस्तरां एसोसिएशन ने मिलकर यह घोषणा की है।

नई दिल्ली। दिल्ली में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली नगर निगम और होटल व लॉजिंग हाउस एसोसिएशन ने 20 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। निगम के करोल बाग और नजफगढ़ जोन के तहत आने वाले होटल व रेस्तरां में यह सुविधा होगी।

निगम के साथ मिलकर लाजिग हाउस व होटल व रेस्तरां एसोसिएशन ने मिलकर यह घोषणा की है। इसके तहत मतदान करने के बाद 24 घंटे के भीतर उंगली पर लगी स्याही दिखाने पर बिल पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वोट रखता है मायने

करोल बाग क्षेत्र के उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने कहा कि हमारा मानना है कि हर वोट मायने रखता है, और नागरिकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए दिल्ली नगर निगम का जन स्वास्थ्य विभाग करोल बाग क्षेत्र के व्यापारियों से संपर्क कर रहा है। उन्होंने कहा कि ₹इस विशेष छूट की पेशकश करके, हम अधिक लोगों को वोट डालने और हमारे देश के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं।

किराए के कमरे में मिलेगी छूट

नजफगढ़ क्षेत्र के उपायुक्त बादल कुमार ने बताया कि होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन, महिपालपुर द्वारा कमरे के किराए पर 20 प्रतिशत की छूट देने के लिए कहा गया है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए योग्य मतदाता वोट डालने के 24 घंटे के अंदर अपना आवास बुक करके और अपनी उंगली पर स्याही के निशान का प्रमाण प्रस्तुत करके छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में मतदाताओं की भागीदारी के महत्व को बढ़ावा देती है।

इस दिन के लिए है सिर्फ छूट

यह छूट केवल दिल्ली में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए ही लागू होगी। उन्होंने बताया कि लाजिंग हाउस ओनर्स एसोसिएशन से संबद्ध होटलों में आवास बुक करते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि दिल्ली होटल और रेस्तरां ओनर्स एसोसिएशन के तहत प्रतिष्ठानों में बुकिंग करने वालों को समान 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

रेड लाइन पर रफ्तार भर रहीं आठ कोच की मेट्रो ट्रेनें, फिर भी यात्रियों को हो रही ये समस्या

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो राजधानी वासियों की लाइफलाइन बनी हुई है। ब्लू व यलो लाइन की तरह दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर भी अब सभी आठ कोच की मेट्रो ट्रेनें रफ्तार भर रही हैं। इसके बावजूद यात्रियों के सामने मेट्रो की कम फ्रीक्वेंसी समस्या बनी हुई है। इस कॉरिडोर की 39 में से 37 मेट्रो आठ कोच की ट्रेन में तब्दील की जा चुकी हैं।

नई दिल्ली। ब्लू व यलो लाइन की तरह दिल्ली मेट्रो के सबसे पुराने कॉरिडोर रेड लाइन (रिठाला-न्यू बस अड्डा गाजियाबाद) पर भी अब सभी आठ कोच की मेट्रो ट्रेनें ही रफ्तार भर रही हैं। इसका कारण यह है कि इस कॉरिडोर पर इस्तेमाल होने वाली दो मेट्रो ट्रेनों को छोड़कर बाकी अन्य सभी ट्रेनें आठ कोच की ट्रेन में तब्दील हो गई हैं।

मेट्रो के व्यस्त कॉरिडोर में शुमार है रेड लाइन

इससे रेड लाइन की मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर पहले से आसान हुआ है। लेकिन इस कॉरिडोर पर मेट्रो की कम फ्रीक्वेंसी अभी समस्या बनी हुई है। रेड लाइन दिल्ली मेट्रो के व्यस्त कॉरिडोर में शुमार है। लेकिन पहले इस कॉरिडोर पर छह कोच की मेट्रो ट्रेनों का परिचालन होता था।

इस वजह से इस कॉरिडोर की मेट्रो में यात्रियों की अधिक होती थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ब्लू, यलो व रेड लाइन के लिए वर्ष 2018 में 120 कोच खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। अप्रैल 2021 तक ये सभी कोच दिल्ली पहुंच गए थे।

यलो व ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे व्यस्त कारिडोर है। इसलिए सबसे पहले ब्लू लाइन पर चलने वाली छह कोच की नौ मेट्रो व यलो लाइन की 24 मेट्रो में दो-दो अतिरिक्त कोच जोड़े गए। इसके बाद 34.55 किलोमीटर लंबी रेड लाइन की मेट्रो को नवंबर 2022 में आठ कोच में तब्दील करने का काम शुरू हुआ।

आखिरी समय में लैंडिंग, सिर्फ दो मिनट का बचा था ईंधन; अटकी हुई थीं फ्लाइट में बैठे लोगों की सांसें

परिवहन विशेष न्यूज

इंडिगो की फ्लाइट में यात्रा कर रहे यात्रियों की एकाएक सांसे अटक गई। विमान अयोध्या से प्रस्थान कर दिल्ली आ रहा था। इस दौरान खराब मौसम की वजह से पायलट उड़ान को लैंड नहीं कर पा रहे थे। इसे लेकर यात्रियों को विमान में ईधन को लेकर चिंता सताने लगी। इस बीच डायवर्ट होने के बाद विमान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा गया।

नई दिल्ली। तेज हवा के साथ जिस समय दिल्ली में वर्षा हो रही थी। उस समय दिल्ली के आसमान में उड़ रही एक उड़ान में बैठे लोगों की सांसें अटकी हुई थी। क्योंकि खराब मौसम की वजह से पायलट उड़ान को लैंड नहीं कर पा रहे थे और यात्रियों को इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं उड़ान का ईंधन न खत्म हो जाए।

क्योंकि उसी उड़ान में यात्रा कर रहे पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा, दिल्ली) सतीश कुमार ने दावा किया है कि इंडिगो की उड़ान, जो अयोध्या से प्रस्थान कर दिल्ली आ रही थी, डायवर्ट होने के बाद जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरी तो उसमें सिर्फ एक या दो मिनट का ईंधन बचा था।

उड़ान में पर्याप्त ईंधन था- एयरलाइन

इसी उड़ान में यात्रा कर रहे एक सेवानिवृत्त पायलट ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं एयरलाइन ने सोमवार को इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उड़ान में पर्याप्त ईंधन था। उड़ान के अनुभव को भयावह बताते हुए सतीश कुमार ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा कि शनिवार शाम को तीन बजकर 25 मिनट पर उड़ान अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हुई।

शाम साढ़े चार बजे उड़ान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उससे 15 मिनट पहले पायलट ने घोषणा की कि दिल्ली में मौसम खराब है। इस दौरान पायलट द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि विमान में 45 मिनट तक का ईंधन है।

पोस्ट में उन्होंने बताया कि दो बार लैंडिंग का प्रयास किया गया लेकिन खराब मौसम की वजह से लैंडिंग नहीं हो सकी। साढ़े पांच बजे उन्हें बताया गया कि उड़ान को चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया है।इस बीच कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। एक क्रू मैंबर को उल्टियां तक आने लगी थीं।

उड़ान में 45 मिनट का ईंधन बचे होने की घोषणा के 115 मिनट बाद शाम छह बजकर दस मिनट पर उड़ान चंडीगढ़ लैंड हुई।लैंड होने के बाद उन्हें क्रू मेंबर से पता लगा कि उड़ान की बिल्कुल आखिरी समय पर लैंडिंग करवाई गई है।विमान में सिर्फ एक से दो मिनट का ही ईंधन बचा था।

फ्लाइट में ईंधन की कमी नहीं थी- इंडिगो एयरलाइन

इसी उड़ान में यात्रा कर रहे सेवानिवृत्त पायलट शक्ति लुंबा ने एक्स पर पोस्ट कर मामले को घोर लापरवाही बताया है और इंडिगो की ओर से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बताते हुए जांच की मांग की है। इंडिगो एयरलाइन प्रवक्ता ने सोमवार को मामले में कहा है कि उड़ान में ईंधन की कमी नहीं थी।

उन्होंने कहा कि अयोध्या और दिल्ली के बीच चलने वाली इंडिगो की उड़ान को दिल्ली में खराब मौसम के कारण चंडीगढ़ की ओर डायवर्ट कर दिया गया था।पायलट ने नियम के अनुसार, आकाश में एक चक्कर लगाया।उड़ान को वैकल्पिक एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए उड़ान में पर्याप्त ईंधन था।यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।

मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर, अभी नहीं रहेगा गर्मी का दौर; आईएमडी का बारिश को लेकर भी अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से अभी राजधानी में गर्मी से राहत का दौर बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह ही अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो जल्द एक और पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है। इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी नजर आएगा।

नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अभी राजधानी में गर्मी से राहत का दौर बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह ही अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो जल्द एक और पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है।

इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों पर भी नजर आएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में दो दिन और आंधी और वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

तापमान में तेजी से इजाफा नहीं होगा

मौसम विभाग का अनुमान है कि इस पूरे सप्ताह मौसम की कोई न कोई गतिविधि लगातार होती रहेगी। इससे अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा नहीं होगा। अगले तीन दिनों के बीच हवा की रफ्तार 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है तो उसके बाद दो दिन बीच-बीच में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। इसके चलते आमतौर पर अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।

तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 19 और 20 अप्रैल को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा होगी।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक देने के कारण होगा।

कौशांबी डिपो के बाहर कारोबारी की कार से 3.62 लाख मिले, रुपये जब्त कर पुलिस जांच में जुटी

लिंक रोड थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर को कौशांबी डिपो के बाहर यूटर्न पर चेकिंग के दौरान कारोबारी की कार से तीन लाख 62 हजार रुपये मिले हैं। वह रुपये के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने रुपये जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को लिंक रोड थाना क्षेत्र में कौशांबी डिपो के बाहर यूटर्न पर बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही थी।

गाजियाबाद। लिंक रोड थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर को कौशांबी डिपो के बाहर यूटर्न पर चेकिंग के दौरान कारोबारी की कार से तीन लाख 62 हजार रुपये मिले हैं। वह रुपये के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने रुपये जब्त कर लिए।

पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि मंगलवार को लिंक रोड थाना क्षेत्र में कौशांबी डिपो के बाहर यूटर्न पर बैरियर लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बलेनो कार को चेकिंग के लिए रोका गया। कार की तलाशी ली गई तो तीन लाख 62 हजार रुपये मिले।

पुलिस कार सवार को लिंक रोड थाने ले आई। कार मालिक की पहचान राधेकृष्ण लेन कौशांबी के मयंक जैन के रूप में हुई है। उनकी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री है। वह फैक्ट्री जा रहे थे। उनसे रुपये के बारे में जानकारी की गई। वह इसका हिसाब नहीं दे सके। पुलिस ने रुपये जब्त कर लिए हैं। इसकी रिपोर्ट बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दी है।

रिजल्ट में देरी से अटका 96 छात्रों का स्कूलों में प्रवेश, अभिभावक परेशान

परिवहन विशेष न्यूज

परीक्षा के परिणाम की देरी के कारण 96 छात्रों का इंटर कॉलेज में प्रवेश अटका हुआ है। परीक्षा का आयोजन छह नवंबर को हुआ था। परिषदीय स्कूलों के छात्रों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस सत्र के लिए 721 छात्रों ने आवेदन किया था। पांच महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी परिणाम नहीं आने से छात्र के साथ उनके अभिभावक भी परेशान है।

नोएडा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल बीतने के बाद भी जारी नहीं हो पाया है। परीक्षा के परिणाम की देरी के कारण 96 छात्रों का इंटर कॉलेज में प्रवेश अटका हुआ है। परीक्षा का आयोजन छह नवंबर को हुआ था। पांच महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी परिणाम नहीं आने से छात्र के साथ उनके अभिभावक भी परेशान है।

इस परीक्षा में सफल आठवीं के छात्रों को हर महीने शासन की ओर से एक हजार रुपये की राशि दी जाती है। नौवीं से लेकर 12वीं तक छात्रों को पढ़ाई के लिए 48 हजार रुपये मिलते हैं। परिषदीय स्कूलों के छात्रों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस सत्र के लिए 721 छात्रों ने आवेदन किया था।

राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जनपद में 96 सीट रिर्जव है, जिसमें दो सीट एसटी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अभिभावक राकेश ने बताया कि परीक्षा का परिणाम नहीं आने के कारण वह छात्र का प्रवेश नहीं करा पा रहे हैं। नए सत्र को शुरु हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्चे का प्रवेश नहीं हो पाया है। इस परीक्षा में बच्चे का चयन हो सकता है। बच्चे के 70 प्रतिशत से अधिक प्रश्न सही थे।

पिछले सत्र में 35 छात्रों को मिला लाभ

पिछले सत्र में पहली बार जनपद में सभी छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें से 35 छात्रों ने ही सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लिया। मार्च में सभी छात्रों के खातों में 12 हजार रुपये की राशि भेज दी गई है, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 35 छात्रों को भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है।

55 प्रतिशत वाले ही कर पाए आवेदन

छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 50 प्रतिशत अंक पिछली कक्षा में होना अनिवार्य था। सत्र 2022-23 में 96 में से एक ही छात्र का चयन इस परीक्षा में हो पाया था। उस छात्र ने भी प्रवेश नहीं लिया था।

गाजियाबाद आ रहीं बसपा सुप्रीमो, रामलीला मैदान में मायावती करेंगी चुनावी सभा

लोकसभा के बसपा प्रत्याशी नंदकिशोर पुण्डीर के चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए 21 अप्रैल को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती गाजियाबाद आ रही हैं। बसपा प्रत्याशी नंदकिशोर पुण्डीर ने बताया कि कविनगर स्थित रामलीला मैदान में चुनावी सभा होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में कुछ विभागों ने चुनावी रैली को लेकर अनापत्ति भी जारी कर दी गई है।

गाजियाबाद। लोकसभा के बसपा प्रत्याशी नंदकिशोर पुण्डीर के चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए 21 अप्रैल को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती गाजियाबाद आ रही हैं। बसपा प्रत्याशी नंदकिशोर पुण्डीर ने बताया कि कविनगर स्थित रामलीला मैदान में चुनावी सभा होगी।

इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में कुछ विभागों ने चुनावी रैली को लेकर अनापत्ति भी जारी कर दी गई है। बसपा जिला अध्यक्ष दयाराम सेन ने इसकी पुष्टि की है कि रामलीला मैदान कविनगर में ही चुनावी सभा होगी।

कविनगर रामलीला मैदान में होगी सभा

इससे पहले बसपा ने एनडीआरएफ स्थित मैदान और कमला नेहरू नगर स्थित ग्राउंड में चुनावी सभा कराए जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति मांगी थी, लेकिन फिलहाल कविनगर रामलीला मैदान में चुनावी सभा की अनुमति मिलने की पूरी संभावना है। विधानसभा चुनाव में भी मायावती की चुनावी रैली रामलीला मैदान कविनगर में ही हुई थी।

मकान मालिकों और किराएदार को लेकर लिया गया ये फैसला, नियम न मानने पर हो सकती है जेल

अपराध पर अंकुश लगाने व अपराध में लिप्त अपराधियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने मकान मालिकों की भूमिका तय कर दी है। मकान मालिकों को ईकोटेक तीन कोतवाली पुलिस की तरफ से एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि यदि पांच दिन के अंदर मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया तो जेल की हवा खानी होगी।

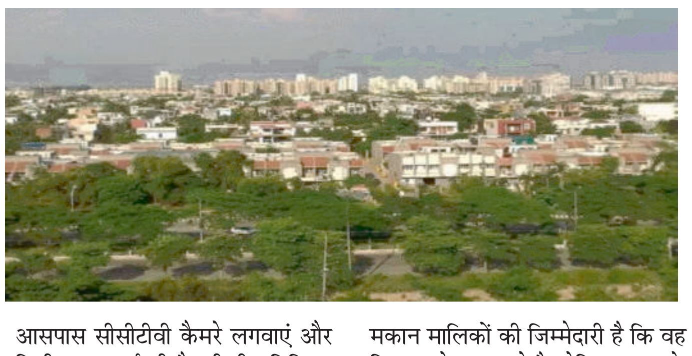

नोएडा। अपराध पर अंकुश लगाने व अपराध में लिप्त अपराधियों की पहचान करने के लिए पुलिस ने मकान मालिकों की भूमिका तय कर दी है। मकान मालिकों को ईकोटेक तीन कोतवाली पुलिस की तरफ से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि पांच दिन के अंदर मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया तो जेल की हवा खानी होगी।

पुलिस मकान मालिकों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई करेगी। यह पहल इसलिए की गई है, जिससे कि किराए के मकान में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

पुलिस ने लिखा पत्र

पुलिस ने पत्र में यह भी लिखा है कि मकान मालिक अपने किराए के मकान के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और निजी सुरक्षागार्ड की तैनाती भी सुनिश्चित करें। यदि मकान मालिक नियमों का पालन नहीं करेंगे और उनके किराए के भवन में कोई आपराधिक घटना होती है जिम्मेदारी मकान मालिक की तय की जाएगी।

ईकोटेक तीन कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि पिछले एक महीने में तीन ऐसे मामले सामने आए जिसमें लड़कियां गायब हुई। स्वजन ने जिस पर आरोप लगाया वह दोषी नहीं निकला। जांच में पता चला कि लड़की अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई।

यदि उक्त किराए के भवन में सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो तुरंत ही यह बात पता चल जाती कि लड़की किस व्यक्ति के साथ गई है। स्वजन के आरोप से निर्दोष व्यक्ति पुलिस के रडार पर आ जाता है। ऐसे में मकान मालिकों की जिम्मेदारी है कि वह किराया तो वसूल रहे है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए है। उनकी भी इसमें जिम्मेदारी है कि वह क्षेत्र को सुरक्षित बनाने में अपनी हिस्सेदारी तय करें।

क्षेत्र में रहते है डेढ़ लाख किराएदार

कोतवाली क्षेत्र के गांव कुलेसरा, हबीबपुर, खेड़ा चौगानपुर, तुस्याना, सुत्याना में करीब डेढ़ लाख किराएदार रहते है। इसमें हबीबपुर व कुलेसरा गांव में रहने वाले किराएदारों की संख्या सबसे अधिक है।

किराए के कमरों में हुई घटनाएं

17 जनवरी को तुगलपुर में किराए पर रहने वाली महिला रचना कुमारी की हत्या।

28 दिसंबर 2022 को नोएडा के फेज दो में किराए के कमरे में रहने वाली युवती से दुष्कर्म।

चुनाव में बनते-बिगड़ते समीकरण के बीच हर बार बदलते हैं नारों के तेवर, खूब जमाते हैं रंग

चुनाव में दो बातें बेहद अहम हैं जिनमें पहली चुनावी चुनावी घोषणाएं और दूसरे चुनावी नारे। ये दोनों बातें चुनाव में रंग जमाते हैं। चुनाव प्रचार में नारों के तेवर जनता की जुबान पर ऐसे चढ़ जाते हैं कि इससे प्रत्याशी की हार-जीत का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्ष 1952 से 2024 तक नारों से पार्टियों की विचारधारा की तस्वीर बनी है।

गाजियाबाद। चुनाव में दो बातें बेहद अहम हैं, जिनमें पहली चुनावी घोषणाएं और दूसरे नारे। आक्रामक प्रचार शैली, स्टार प्रचारक और चमक-दमक के साथ नारे चुनाव में जीत-हार को तय करने में खास रोल निभाते हैं। चुनाव के बनते-बिगड़ते समीकरणों के बीच चुनावी नारे खूब रंग जमाते रहे हैं।

शुरुआती चुनाव से मौजूदा दौर तक चुनावी नारे ही सियासी दलों की विचारधारा की तस्वीर को जनता के बीच साफ करती हैं। इन्हीं नारों की पतवार के सहारे कई पार्टियों की नैया भी पार लगी है। लोकसभा चुनाव के लिए नारों का शोर गली-मोहल्लों में भले ही न सुनाई दे रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंच बना रहे हैं। इनका असर पहले से अधिक प्रभावी है। आजादी के बाद हुए आम चुनाव से अभी तक नारों के तेवर ने बनते बिगड़ते समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

कब जुबान पर चढ़ा कौन सा नारा?

वर्ष 1952 में
खरा रुपैया चांदी कौ, राज महात्मा गांधी कौ।
देश की जनता भूखी है, यह आजादी झूठी है
वर्ष 1957 में
जली झोपड़ी भागे बैल, यह देखा दीपक का खेल, जिस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं।
वर्ष 1962 में, Iजाटव-मुस्लिम भाई-भाई, बाकी कौम कहां से आई।
सिंहासन खाली करो जनता आती है।
वर्ष 1967 में
जय जवान जय किसान।
वर्ष 1977 में
बेटा कार बनाएगा, मां सरकार बनाएगी।
जमीन गर्क चकबंदी में, मकान ढह गया हटबंदी में।
दरवाजे पर खड़ी औरतें चिल्लाएं, मेरा मर्द गया नसबंदी में।
वर्ष 1980 में
इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, का नारा लगा।
वर्ष 1984 में
जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा।
उठे करोड़ों हाथ हैं, राजीव जी के साथ हैं।
वर्ष 1996 में
'सबको देखा बारी-बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।'
महंगाई जो रोक न पाई वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।
वर्ष 2004 में
शाइनिंग इंडिया, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।
वर्ष 2014 में
'अबकी बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी।
वर्ष 2019 में
'सबका साथ सबका विकास', 'मोदी है तो मुमकिन है।
मोदी हटाओ, देश बचाओ, अब होगा न्याय।
वर्ष 2024 में
मोदी की गांरटी, अबकी पार 400 पार।
कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात

राजनीति में भी चमके मीडिया के सितारे

प्रो. संजय द्विवेदी

आजादी के आंदोलन में तो मीडिया को एक तंत्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रायः सभी वरिष्ठ राजनेता पत्रकारिता से जुड़े और उजली परंपराएं खड़ी कीं। बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चन्द्र बोस, महामना मदनमोहन मालवीय, पंडित नेहरू सभी पत्रकार रहे।

> “ मूलतः पत्रकारिता से सार्वजनिक जीवन में आने वाले मोतीलाल वोरा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल ने रायपुर से 'दैनिक महाकौशल' अखबार निकाला। भाजपा के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के अध्यक्ष रहे लखीराम अग्रवाल ने बिलासपुर से 'लोकस्वर' अखबार निकाला।

इन दिनों देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जाहिर है राजनीति का आकर्षण प्रबल है। सिने कलाकार, साहित्यकार, वकील, न्यायाधीश, खिलाड़ी, गायक, उद्योगपति सब क्षेत्रों के लोग राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। ऐसा ही हाल पत्रकारिता के सितारों का भी है। मीडिया और पत्रकारिता के अनेक चमकीले नाम राजनीति के मैदान में उतरे और सफल रहे।

आजादी के आंदोलन में तो मीडिया को एक तंत्र की तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रायः सभी वरिष्ठ राजनेता पत्रकारिता से जुड़े और उजली परंपराएं खड़ी कीं। बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चन्द्र बोस, महामना मदनमोहन मालवीय, पंडित नेहरू सभी पत्रकार रहे। आजादी के बाद बदलते दौर में पत्रकारिता और राजनीति की राहें अलग-अलग हो गईं, लेकिन सत्ता का आकर्षण बढ़ गया। जनपक्ष, राष्ट्र सेवा की पत्रकारिता अब आजाद भारत में राष्ट्र निर्माण का भाव भरने में लगी थी। सेवा राजनीति के माध्यम से भी की जा सकती है, यह भाव भी प्रबल हुआ।

मूल्यों पर 'अटल' रहने वाले 'वाजपेयी'

राजनीतिक दलों से संबंधित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के अलावा मुख्यधारा की पत्रकारिता से भी लोग राजनीति में आए, जिसमें सबसे खास नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है, जो 'वीर अर्जुन' जैसे दैनिक अखबार के संपादक रहे। इसके साथ ही वे 'स्वदेश', 'पांचजन्य' और 'राष्ट्रधर्म' के भी संपादक रह चुके थे। वह जहां संसदीय राजनीति के लंबे अनुभव के साथ प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रहे, तो वहीं भाजपा के वह संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी भी 'हिंदुस्तान समाचार' और 'ऑर्गनाइजर' से जुड़े रहे, फिर राजनीति में आए।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे द्वारिका प्रसाद मिश्र दैनिक 'लोकमत', साप्ताहिक 'सारथी' और 'श्री शारदा' के संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शंभूनाथ शुक्ल बाद में बने मध्यप्रदेश में मंत्री और सांसद रहे। 'विशाल भारत' के संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी के शिष्य रहे बालकृष्ण शर्मा नवीन 'प्रताप' के संपादक रहे और कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे। महाराष्ट्र का दर्डा परिवार राजनीति में अग्रणी रहा। 'लोकमत' समाचार के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा, राजेन्द्र दर्डा और विजय दर्डा सांसद, विधायक और मंत्री रहे। 'विजया कर्नाटक' और 'कन्नड़ प्रभा' अखबार से जुड़े रहे प्रताप सिम्हा भाजपा से दो बार लोकसभा पहुंचे। उनका नाम चर्चा में तब आया, जब उनके द्वारा अनुमोदित विजिटर पास से दो युवकों ने नई संसद में पहुंच कर हंगामा किया।

मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सितारों की जगमगाहट

मूलतः पत्रकारिता से सार्वजनिक जीवन में आने वाले मोतीलाल वोरा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल ने रायपुर से 'दैनिक महाकौशल' अखबार निकाला। भाजपा के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के अध्यक्ष रहे लखीराम अग्रवाल ने बिलासपुर से 'लोकस्वर' अखबार निकाला। बिलासपुर के पत्रकार बीआर यादव मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री और चार बार विधायक रहे। बिलासपुर के ही रहने वाले कवि, पत्रकार श्रीकांत वर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 'दिनमान' के संपादक मंडल में रहने के बाद राजनीति में आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले चंदूलाल चंद्राकर दैनिक 'हिन्दुस्तान' के संपादक रहे। बाद में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। राजनांदगांव के पत्रकार लीलाराम भोजवानी छत्तीसगढ़ सरकार में श्रम मंत्री रहे। 'देशबन्धु' में पत्रकारिता का पाठ पढ़ने वाले चंद्रशेखर साहू छत्तीसगढ़ से सांसद, मंत्री और विधायक रहे। मध्यप्रदेश में सीहोर के पत्रकार शंकर लाल साहू विधायक रहे। त्रिभुवन यादव पिपरिया से विधायक चुने गए। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और दो बार विधायक चुने गए विष्णु राजोरिया मूलतः पत्रकार ही हैं, बाद में उन्होंने 'शिखर वार्ता' पत्रिका भी निकाली। मप्र में ही केएन प्रधान सांसद, विधायक और मंत्री भी रहे। नागपुर के अंग्रेजी अखबार 'हितवाद' के प्रकाशन करने वाले बनवारी लाल पुरोहित कांग्रेस और भाजपा दोनों से लोकसभा पहुंचे। संप्रति वे पंजाब के राज्यपाल हैं।

भाजपा हो या कांग्रेस, सबने दिये मौके

कांग्रेस ने राजीव शुक्ला, प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी, कुमार केतकर, विजय दर्डा आदि को राज्यसभा से नवाजा। राजीव शुक्ला मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वरिष्ठ पत्रकार संजय निरुपम लोकसभा पहुंचे और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 'सामना' के संपादक संजय राऊत अपने धारदार बयानों के लिए लोकप्रिय हैं, वे भी राज्यसभा सदस्य हैं। जनता दल (यू) ने प्रभात खबर के संपादक रहे हरिवंश को दो बार राज्यसभा भेजा, वह इन दिनों राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। 'ऑर्गनाइजर' के संपादक रहे श्री के.आर.मलकानी बाद में राज्यसभा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने चंदन मित्रा, दीनानाथ मिश्र, बलबीर पुंज, राजनाथ सिंह सूर्य, नरेन्द्र मोहन, प्रभात झा, तरुण विजय, स्वप्नदास गुप्ता को राज्यसभा भेजा। इनमें मित्रा बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि पुंज और झा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। प्रभात झा मध्यप्रदेश भाजपा के चर्चित अध्यक्ष भी रहे। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में रह चुके वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर किशनगंज से कांग्रेस से लोकसभा पहुंचे। बाद में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा और विदेश राज्य मंत्री बनाया।

भाषाई पत्रकारों को भी मिले अवसर

तृणमूल कांग्रेस ने हाल में ही अंग्रेजी की पत्रकार सागरिका घोष को राज्यसभा भेजा है। इसके पूर्व उर्दू पत्रकारिता से जुड़े रहे नदीमुल हक भी राज्यसभा में पहुंचे। हिंदी अखबार 'सन्मार्ग' के मालिक विवेक गुप्ता तृणमूल से सांसद भी रहे, अब विधानसभा में हैं। कुणाल घोष भी इसी दल से राज्यसभा पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश कौशिक भी मूलतः पत्रकार हैं। वह दिल्ली और शिमला में पत्रकारिता की लंबी पारी के बाद राजनीति में आए। हरियाणा के अंबाला लोकसभा क्षेत्र से 2014 में भाजपा सांसद चुने गए अश्विनी कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन 'पंजाब केसरी' के माध्यम से की गई उनकी धारदार पत्रकारिता लोगों के जेहन में है। 'इकोनॉमिक टाइम्स' में रहे देवेश कुमार बिहार में भाजपा से विधान परिषद में है और प्रदेश महामंत्री भी हैं। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु भी दैनिक 'हरिभूमि' के संपादक, प्रकाशक रहे हैं। उर्दू के पत्रकार शाहिद सिद्दीकी (नई दुनिया) सपा से, तो मीम अफजल (अखबार-ए-नौ) कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे। आंध्र प्रदेश से 'वार्ता' के संपादक गिरीश सांघी कांग्रेस से राज्यसभा हो आए। पत्रकारिता से जुड़े रहे तेलंगाना के के. केशवराव कांग्रेस और टीआरएस दोनों दलों से राज्यसभा जा चुके हैं। कोलकाता के पत्रकार अहमद सईद मलीहाबादी भी राज्यसभा पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड से एजाज अली भी राज्यसभा (2008 से 2010) में रहे। कुछ राजनीति की देहरी से भी लौट आए, जैसे वरिष्ठ पत्रकार उदयन शर्मा (कांग्रेस) और सीमा मुस्तफा जनता दल के टिकट पर लोकसभा नहीं पहुंच सके।

राजनीति के मंच पर ऐसे अनेक सितारे चमके और अपनी जगह बनाई। तमाम ऐसे भी थे, जो पार्टी के प्रवक्ता या बौद्धिक कामों से जुड़े रहे। तमाम अज्ञात ही रह गये। राजनीति वैसे भी एक कठिन खेल है, संभावनाओं से भरा भी। किंतु सबको इसका फल मिले यह जरूरी नहीं। बावजूद इसके इसका आकर्षण कम नहीं हो रहा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी कहते थे, ₹पत्रकार की पोलिटिकल लाइन तो ठीक है, पर पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए।₹ किंतु यह लक्ष्मण रेखा भी टूट रही है। क्यों इस पर सोचिए जरूर।

2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट अगले महीने हो सकती है लॉन्च, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी ये पॉपुलर हैचबैक

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 2024 Maruti Suzuki Swift में कई नए अपडेट मिलने वाले हैं। अपडेटेड मॉडल का नया अवतार पहले ही विदेशों में लॉन्च किया जा चुका है और इसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड दिए गए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 2024 Maruti Suzuki Swift में कई नए अपडेट मिलने वाले हैं। अपडेटेड स्विफ्ट में नए डिजाइन वाला फ्रंट बम्पर और नई ग्रिल के साथ-साथ अपडेटेड हेडलैंप और एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट (डीआरएल) शामिल हैं।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 2024 Maruti Suzuki Swift में कई नए अपडेट मिलने वाले हैं। अपडेटेड मॉडल का नया अवतार पहले ही विदेशों में लॉन्च किया जा चुका है और इसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड दिए गए हैं। हालाँकि, यह संभावना है कि इंडिया-स्पेक मॉडल में बदलाव किए जाएंगे। आइए, जान लेते हैं कि हम फ्रेस हैच से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

अपडेटेड स्विफ्ट में नए डिजाइन वाला फ्रंट बम्पर और नई ग्रिल के साथ-साथ अपडेटेड हेडलैंप और एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट (डीआरएल) शामिल हैं। सुजुकी का लोगो अब बोनट के टॉप पर प्रमुखता से स्थित है, जबकि किनारों पर नए डिजाइन वाले डुअल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं। उल्लेखनीय अपडेट में ब्लैक-आउट ओआरवीएम, रूफ और पिलर भी शामिल हैं।

पीछे की ओर जाएंगे, तो इसमें एक नया डिजाइन किया गया टेलगेट और नीचे एक स्किड प्लेट के साथ एक नया बम्पर है। इसके अतिरिक्त, इसमें स्टॉप लैंप के साथ एक इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, स्पेसिफिक सी-आकार के डीआरएल के साथ एलईडी टेल लाइट्स होंगे। हालांकि, यह संभावना है कि इंडिया-स्पेक स्विफ्ट विदेशों में बेची जाने वाली स्विफ्ट के समान नहीं होगी और इसमें थोड़े अलग बम्पर के साथ कुछ अन्य बदलाव हो सकते हैं।

अपडेटेड फीचर्स

टेक्नोलॉजी और आराम के मामले में केबिन को महत्वपूर्ण अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। नई स्विफ्ट मारुति सुजुकी के बलेनो और फ्रोंक्स मॉडल से प्रेरणा ले सकती है, जिसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है।

सेफ्टी के लिहाज से ग्लोबल स्विफ्ट में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटर, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ एबीएस मिल सकता है। इसके अलावा ये एडास फीचर्स से भी लैस हो सकती है।

इंजन

जापान में उपलब्ध स्विफ्ट में एक नई Z-सीरीज 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल मोटर है, जो 82 hp और 108 Nm का टॉर्क पैदा करती है। इसमें CVT ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है। डीसी सिंक्रोनस मोटर के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण भी है, जो 3.1 एचपी और 60 एनएम टॉर्क जोड़ता है। फ्यूल एफिशियंसी के संदर्भ में स्टैंडर्ड स्विफ्ट और माइल्ड-हाइब्रिड मॉडल से डब्ल्यूएलटीपी साइकिल के अनुसार क्रमशः 23.4 किमी प्रति लीटर और 24.5 किमी प्रति लीटर की यात्रा कर सकते हैं। यह देखना बाकी है कि इंडिया-स्पेक मॉडल को हाइब्रिड तकनीक मिलेगी या नहीं।

FY 2025 में तेजी से बिछेगा सड़कों का जाल, ICRA ने कहा- 13,000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है आंकड़ा

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में निष्पादन की गति को परियोजनाओं की एक स्वस्थ पाइपलाइन सरकार द्वारा बढ़े हुए पूंजी परिव्यय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थन मिलेगा। इक्रा के अनुसार मंत्रालय की प्रोजेक्ट अवार्ड पाइपलाइन मार्च 2024 तक 45000 किमी से ऊपर अच्छी है।

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को कहा कि 2023-24 में 20 प्रतिशत का मजबूत विस्तार दर्ज करने के बाद, चालू वित्त वर्ष में भारत में सड़क निष्पादन 5-8 प्रतिशत बढ़कर 12,500-13,000 किमी होने की संभावना है।

रिपोर्ट में क्या खास?

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में निष्पादन की गति को परियोजनाओं की एक स्वस्थ पाइपलाइन, सरकार द्वारा बढ़े हुए पूंजी परिव्यय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थन मिलेगा। इक्रा ने नोट किया कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में लंबे समय तक मानसून के कारण वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में सड़क निष्पादन प्रभावित हुआ, जिससे उत्पादक दिन प्रभावित हुए।

प्रोजेक्ट अवार्ड पाइपलाइन से बेहतर स्थिति

इक्रा के अनुसार, मंत्रालय की प्रोजेक्ट अवार्ड पाइपलाइन मार्च 2024 तक 45,000 किमी से ऊपर अच्छी है। इसमें कहा गया है कि भारतमाला परियोजना चरण 1 (बीएमपी) के संशोधित लागत अनुमानों के लिए कैबिनेट से मंजूरी में देरी के कारण वित्त वर्ष 24 में पुरस्कार देने पर काफी असर पड़ा है। नतीजतन, वित्त वर्ष 2024 में कुल पुरस्कार 31 प्रतिशत घटकर 8,551 किमी हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 12,375 किमी था।

महिंद्रा ने लॉन्च की 9 सीटों वाली एसयूवी, कितनी है कीमत और फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। Mahindra की ओर से नौ सीटों (Mahindra 9 Seater SUV) के साथ नई एसयूवी को आधिकारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया गया है। नौ सीटों वाली इस नई एसयूवी में किस तरह की खूबियों को दिया गया है और इसे किस कीमत पर उपलब्‍ध करवाया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। कई बेहतरीन एसयूवी को भारतीय बाजार में ऑफर करने वाली कंपनी महिंद्रा की ओर से अब एक और एसयूवी को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से नई एसयूवी को नौ सीटों के साथ लाया गया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि महिंद्रा किस नई एसयूवी को नौ सीटों के साथ लाई है। इसमें कैसे फीचर्स दिए गए हैं और इसकी क्या कीमत रखी गई है।

लॉन्‍च हुई नई एसयूवी

महिंद्रा की ओर से Bolero Neo+ के नए वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इस एसयूवी को नौ सीटों (9 seater SUV) के विकल्प के साथ लाया गया है। इस एसयूवी में नौ सीटों के विकल्प के साथ ही दमदार इंजन और बेहतरीन फीचर्स को भी ऑफर किया जा रहा है। इस एसयूवी में फ्रंट में दो, मिडल में तीन और रियर में चार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है।

कैसे हैं फीचर्स

महिंद्रा की नई Bolero Neo+ SUV में प्रीमियम इटालियन इंटीरियर, प्रीमियम फैब्रिक, 22.8 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी, ऑक्स कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, हाइट एडजस्ट ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर पावर विंडो, एबीएस, ईबीडी, ड्यूल एयरबैग, इंजन इमोबिलाइजर, ऑटो डोर लॉक, एक्स शेप बंपर और फ्रंट ग्रिल के साथ क्रोम इंसर्ट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कितना दमदार इंजन

कंपनी ने इस एसयूवी में 2.2 लीटर एम-हॉक डीजल इंजन दिया है। जिसके साथ माइक्रो हाइब्रिड तकनीक को दिया गया है। इस तकनीक के कारण एसयूवी का माइलेज (Bolero Neo Plus Milage) काफी बेहतर हो जाता है। इस इंजन के साथ एसयूवी में छह स्पीड गियरबॉक्स और रियर व्हील ड्राइव को दिया गया है।

कितनी है कीमत

महिंद्रा Bolero Neo+ 9 सीटों वाली इस एसयूवी (Mahindra 9 seater SUV) को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके पी4 (P4) वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 11.39 लाख रुपये रखी गई है। जबकि इसके पी10 (P10) वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है।

निसान मैगनाइट के इस पार्ट में आई खराबी, कंपनी ने जारी किया रिकॉल

जापानी वाहन निर्माता Nissan की ओर से भारतीय बाजार में सब फोर मीटर सेगमेंट में एसयूवी के तौर पर Magnite को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इकलौती एसयूवी Magnite के एक पार्ट में खराबी की जानकारी मिली है। जिसके बाद इसे वापिस बुलाया गया है। Nissan Magnite को किस खराबी के बाद Recall किया गया है।

नई दिल्ली। जापान की प्रमुख वाहन निर्माता Nissan की ओर से Magnite को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। कंपनी को इस एसयूवी में खराबी की जानकारी मिली है। जिसके बाद इसकी कुछ यूनिट्स को रिकॉल किया गया है। किस खराबी की जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने अपनी एसयूवी को रिकॉल किया है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

जारी हुआ Recall

Nissan ने Magnite SUV के लिए Recall जारी किया है। कंपनी की इस एसयूवी में सेंसर की खराबी की जानकारी मिलने के बाद इसकी कुछ यूनिट्स को वापिस बुलाया गया है। कंपनी की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि कितनी यूनिट्स में खराबी की जानकारी मिलने के बाद रिकॉल किया गया है।

पहली बाइक खरीद रहे हैं, तो इन चीजों का रखें ध्यान; मिलेगी बेहतरीन डील

भारतीय बाजार में बहुत सारे दोपहिया वाहन उपलब्ध हैं जो वाइड प्राइस स्प्रेक्ट्रम में उपलब्ध हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और एक नई मोटरसाइकिल या स्कूटर पर कितना खर्च करने को तैयार हैं। इसके साथ ही अपनी पसंद और उपयोग के आधार पर विचार करें कि आपको किस प्रकार की मोटरसाइकिल की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। अपनी पहली टू-व्हीलर खरीदते समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप निकट भविष्य में नई मोटरसाइकिल या स्कूटर घर लाने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। अपनी सपनों की सवारी खरीदते समय सर्वोत्तम डील पाने के लिए नीचे दिए जरूरी प्वाइंट्स का ध्यान रखें।

अपना बजट सेट करें

भारतीय बाजार में बहुत सारे दोपहिया वाहन उपलब्ध हैं, जो वाइड प्राइस स्प्रेक्ट्रम में उपलब्ध हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और एक नई मोटरसाइकिल या स्कूटर पर कितना खर्च करने को तैयार हैं। एक निर्धारित बजट होने से आपको अपने विकल्पों को कम करने में मदद मिलेगी और आपको उन मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी जो निश्चित मूल्य सीमा के भीतर फिट होते हैं। इससे आप उलझन और अनावश्यक खर्च से बच जाएंगे।

मोटरसाइकिल चुनें

अपनी पसंद और उपयोग के आधार पर विचार करें कि आपको किस प्रकार की मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। ये एक रेगुलर कम्यूटर, क्रूजर, नेकेड स्ट्रीटफाइटर या एडवेंचर टूरर हो सकती है। आप जिस प्रकार की मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसका सही प्रकार से चुनाव करें।

छोटी सी रिसर्च करें

बाइक का चुनाव करने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन डील के लिए रिसर्च करें। डीलर स्तर पर क्या ऑफर और छूट दी जा रही है, यह जांचने के लिए कुछ शोरूम में जाने का प्रयास करें। सीजन सेल, प्रमोशन और ऑफर पर नजर रखें।

डील डन करें

एक बार जब आप निर्माताओं और डीलरों द्वारा उपलब्ध ऑफर और छूट के संबंध में पर्याप्त मात्रा में डेटा एकत्र कर लें, तो उनकी तुलना करें। इसके अलावा, प्रत्येक सौदे की अंतिम कीमतें जानने के लिए बीमा लागत और अन्य परिवर्तनीय लागतों की तुलना करें।

इस साल महिन्दरा लाएगी दो बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी, जानें किसे मिलेगी चुनौती

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की प्रमुख एसयूवी निर्माता Mahindra की ओर से बाजार में कई बेहतरीन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस साल अपने Electric पोर्टफोलियो का विस्तार किया जा सकता है। साल 2024 में महिंद्रा की ओर से किस सेगमेंट में किस Electric एसयूवी को लाने की तैयारी की जा रही है।

नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश की प्रमुख एसयूवी निर्माता Mahindra की ओर से इस साल में दो बेहतरीन Electric एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से इस साल किस सेगमेंट में किस नई Electric एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है।

आएंगी दो Electric एसयूवी

महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही दो नई Electric एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है। दोनों ही इलेक्ट्रिक एसयूवी को कंपनी की ओर से अलग अलग सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। कंपनी की ओर से अभी इन दोनों ही इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

XUV.e8 होगी लॉन्‍च

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित e8 इलेक्ट्रिक एसयूवी को इस साल भारत में लॉन्च किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस साल के आखिर तक इस एसयूवी को भारत में लाया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी मिड साइज सेगमेंट में लाई जा सकती है। XUV.e8 में कंपनी 80kWh की क्षमता की बैटरी को दे सकती है। इसके साथ इसमें लगी मोटर से एसयूवी को 227 से 435 हॉर्स पावर मिल सकती है। इसे ऑल व्हील और टू व्हील ड्राइव के विकल्प के साथ लाया जा सकता है। देश में कई बार इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसमें वर्टिकल एलईडी हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स, टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई फीचर्स को दिया जा सकता है। महिंद्रा की XUV.e8 इलेक्ट्रिक एसयूवी से हुंडई कोना, एमजी जेडएस ईवी को सीधी चुनौती मिल सकती है।

XUV 3XO पर आधारित होगी दूसरी Electric SUV

महिंद्रा की ओर से दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर जिस एसयूवी को लाया जाएगा। वह XUV 3XO पर आधरित होगी। कंपनी की ओर से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को जून, जुलाई के आस पास लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 35 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जा सकता है और इसे मौजूदा XUV400 के नीचे पोजिशन किया जाएगा। इसकी रेंज भी करीब 300 से 400 किलोमीटर के आस पास हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस Electric SUV की कीमत कंपनी 12 से 14 लाख रुपये के बीच रख सकती है। इस एसयूवी से बाजार में मौजूदा टाटा नेक्सन को सीधी चुनौती मिलेगी।

आ रही है XUV 3XO

इस महीने में कंपनी की ओर से XUV 3XO एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी को कंपनी आईसीई के तौर पर ला रही है। जिसके बाद इस पर आधारित इलेक्ट्रिक एसयूवी को लाया जा सकता है।

स्थिर और मजबूत रुपए की आहट

गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 की पहली दो तिमाहियों में रुपए में डॉलर के मुकाबले मात्र 1.0 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों में रुपया-डॉलर विनिमय दर 83.0 रुपए प्रति डॉलर के आसपास स्थिर हो गई। इस प्रकार की स्थिति आम तौर पर अतीत में नहीं देखी गयी है।

इन सब प्रयासों के मद्देनजर सरकार द्वारा प्रोत्साहित सभी क्षेत्रों में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे आयातों पर अंकुश लगेगा व निर्यातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा'...

कई दशकों की लगातार गिरावट के बाद वर्ष 2023-24 में रुपया स्थिर होने लगा है, खासकर इसकी तीसरी और चौथी तिमाही में। हम कह सकते हैं कि वर्ष 2023-24 भारतीय रुपए के लिए बहुत शुभ रहा। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 की पहली दो तिमाहियों में रुपए में डॉलर के मुकाबले मात्र 1.0 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों में रुपया-डॉलर विनिमय दर 83.0 रुपए प्रति डॉलर के आसपास स्थिर हो गई। इस प्रकार की स्थिति आम तौर पर अतीत में नहीं देखी गयी है। हम देखते हैं कि 1980 के दशक से ही रुपए का मूल्य लगातार गिरता रहा है, जब हमारा देश प्रशासित विनिमय दर की व्यवस्था से हटकर बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर आ गया था। यह उल्लेखनीय है कि रुपया-डॉलर विनिमय दर 1982 में 9.46 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर से बढक़र 31 मार्च 2023 में 82.17 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर हो गई थी। इसका अभिप्राय यह है कि 1982 से लेकर मार्च 2023 तक डॉलर में 868.6 प्रतिशत की गिरावट आई है, यानी पिछले 41 सालों में 5.41 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रुपए का अवमूल्यन हुआ है। ऐसा देश में तेजी से बढ़ते आयातों और उससे कहीं कम गति से बढ़ते निर्यातों के कारण हुआ है।

घटता चालू खाता घाटा : पिछले एक साल में, हम माल और सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं। चालू खाते पर घाटा वर्ष 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों में घटकर केवल 28 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत है। चौथी तिमाही के पहले दो महीनों में घाटा अधिशेष में बदल गया है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है, तो पूरे वर्ष के लिए चालू खाते पर घाटा लगभग 30 अरब अमरीकी डॉलर तक कम हो सकता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम हो सकता है, जो वर्ष 2022-23 के चालू खाते पर घाटे (66 बिलियन अमरीकी डॉलर, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत) से बहुत कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन भारतीय मूल के लोगों से आने वाले प्रेषण में वृद्धि से इसकी भरपाई हो रही है। इसी प्रकार, अमरीका और यूरोप में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद, भारतीय मूल के लोगों से आने वाले धन में वृद्धि जारी रही और 2022-23 में 125 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2023-24 में इसके 135 अरब अमरीकी डॉलर होने की संभावना है।

डॉलर की बढ़ रही हैं मुश्किलें : प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही हम डॉलर के मूल्य में निरंतर वृद्धि देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने आपूर्ति के बदले में संयुक्त राज्य अमरीका को सोने में भुगतान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बन गया। युद्ध की समाप्ति के बाद विभिन्न देशों ने अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया और इसके साथ ही दुनिया में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' समाप्त हो गया और इस प्रकार डॉलर दुनिया की सबसे पसंदीदा मुद्रा बन गई। सभी देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का अधिक से अधिक हिस्सा डॉलर के रूप में रखने लगे। लेकिन वर्ष 2000 के बाद अंतरराष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर का महत्व कम होता गया और अब यह लगभग 58 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इतिहास में दुनिया भर के देशों के डॉलर के प्रति आकर्षण के कारण, डॉलर दुनिया की अन्य मुद्राओं, विशेष रूप से विकासशील देशों की मुद्राओं के मुकाबले लगातार मजबूत होता गया। भारत में जहां 1964 में एक डॉलर केवल 4.66 रुपए के बराबर था और अब यह लगभग 83.38 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। शायद इसीलिए दुनिया के सभी देश डॉलर को आरक्षित मुद्रा के रूप में रखने और अपने सभी अंतरराष्ट्रीय भुगतान केवल डॉलर में करने में रुचि रखते हैं। डॉलर की इस बढ़ती मांग के कारण, डॉलर साल दर साल मजबूत होता रहा। हालांकि वर्ष 2000 में अंतरराष्ट्रीय रिजर्व करंसी के रूप में अमरीकी डॉलर का हिस्सा 70 प्रतिशत से घटता हुआ अभी तक मात्र 58 प्रतिशत ही रह गया है, लेकिन अमरीकी फेडरल रिजर्व का दावा है कि अमरीकी डॉलर वैश्विक स्तर पर सबसे पसंदीदा मुद्रा बनी हुई है, लेकिन समझना होगा कि डॉलर की लोकप्रियता में गिरावट निरंतर जारी है।

विडॉलरीकरण का स्पष्ट संकेत : हम देखते हैं कि अधिकांश देश धीरे-धीरे, लेकिन निश्चित रूप से डॉलर व्यापार से दूर जा रहे हैं।

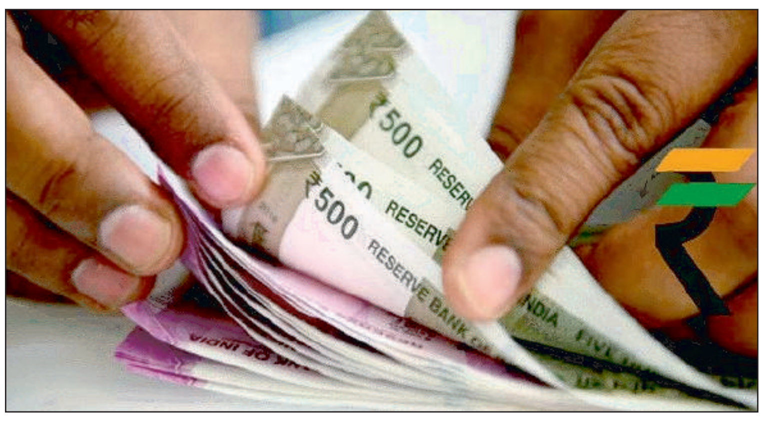

इसके बजाय वे व्यापार का निपटान अपनी मुद्राओं में करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत पहली बार व्यापार निपटान के लिए रुपया-व्यापार तंत्र को बढ़ावा दे रहा है, और लगभग 20 देशों ने, जिनमें अन्य देशों के अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर भी शामिल हैं, इसके लिए सहमति व्यक्त की है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए वास्ट्रो खाते खोले हैं। चीन भी युआन में व्यापार निपटान के लिए जोर दे रहा है। ये वैकल्पिक व्यापार निपटान तंत्र धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं। हालांकि, डॉलर का हिस्सा अभी भी लगभग 58 प्रतिशत है, फिर भी यह बदलाव स्पष्ट और ध्यान देने योग्य है। अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व और व्यापार के निपटान के लिए बड़ी मात्रा में अमरीकी डॉलर रखने की मजबूरी, सामान्य रूप से दुनिया और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए यह बहुत शुभ नहीं रही है। डॉलर का वैश्विक रिजर्व करंसी के रूप में प्रभुत्व विकासशील देशों के लिए शुभ नहीं रहा है। एक तरफ अमरीकी डॉलर की अस्थिरता और दूसरी तरफ उसके बावजूद डॉलरों के भंडार को रखने की मजबूरी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में रूस-यूक्रन संघर्ष और दुनिया में अन्य प्रकार से अशांति और बाधाओं के कारण से कुछ विकासशील देशों और क्षेत्रीय ब्लॉकों द्वारा घरेलू मुद्राओं में व्यापार करने के प्रयासों को मदद मिली है, जिससे अमरीकी डॉलर पर निर्भरता कम हुई है। इसने अमरीकी वैश्विक वित्तीय आधिपत्य के लिए एक बड़ा झटका दिया है। कच्चे तेल के आयात में अमरीकी डॉलर की अनिवार्यता की समाप्ति, गैर-डॉलरीकरण और अंतरदेशीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि की दिशा में चल रहे वैश्विक रुझान को दर्शाती है। सबसे पहले, रूस से कच्चे तेल की बड़ी खरीद और रुपए और गैर-डॉलर मूल्यवर्ग के भुगतान करना, भारत-यूएई द्वारा भारतीय रुपए में समझौता, दक्षिणी विश्व के देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने से विकासशील देशों को बड़े लाभ हुए हैं, जिसमें विनिमय दरों में कमी और अमरीकी डॉलर से जुड़ी अस्थिरता को कम करके व्यापार को अधिक पूर्वानुमानित और स्थिर बनाना शामिल है।

आत्मनिर्भर औद्योगिक नीति का भी मिल रहा लाभ : गौरतलब है कि पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से देश में आयात तेजी से बढ़े हैं, जबकि निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। देश में बढ़ती आमदनियों और औद्योगिक विकास के अभाव में देश में आयात लगातार बढ़ते गए और निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, यह देश में रुपए के अवमूल्यन का एक बड़ा कारण बना। लेकिन वर्ष 2021 में कोरोना महामारी से सीख लेते हुए भारत ने तेजी से आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना शुरू किया है। पीएलआई यानी उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के माध्यम से अब उन सब उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गैरबराबरी की विदेशी प्रतिस्पद्र्धा के कारण बंद हो गए थे। इसके साथ ही साथ नई पीढ़ी के उद्योगों जैसे सोलर विद्युत उपकरण, सेमी कंडक्टर, टेलीकॉम और ड्रोन इत्यादि को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास चल रहा है। इन सब प्रयासों के मद्देनजर सरकार द्वारा प्रोत्साहित सभी क्षेत्रों में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। इन सबके कारण जहां एक ओर आयातों पर अंकुश लगेगा, निर्यातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत का व्यापार घाटा और भुगतान शेष घाटा कम होंगे।

-डा. अश्वनी महाजन

संपादक की कलम से

विस्तार पाते 'संकल्प'

भाजपा के 'संकल्प-पत्र' में कुछ भी नयापन नहीं है। योजनाओं का या तो विस्तार किया गया है अथवा राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई है। भाजपा पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड और लोकप्रियता के भरोसे है। प्रत्यक्ष रेवडियों अथवा मुफ्तखोरी का कोई भी संकल्प नहीं किया गया है। देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए 5 किलो 'मुफ्त अनाज' की योजना 2029 तक जारी रहेगी। यह देश आकलन करेगा कि वह इसे 'मुफ्तखोरी' की जमात में रखता है अथवा इसे सामाजिक-राष्ट्रीय कल्याण की जरूरत मानता है! हालांकि कोरोना-काल के काले-आर्थिक प्रभाव अब समाप्त हो चुके हैं। बहरहाल भाजपा का चुनावी घोषणा-पत्र एक राजनीतिक दस्तावेज होने के बजाय प्रशासनिक कार्यक्रम का रोड मैप अधिक लगता है, ताकि देश स्थिर और सशक्त बना रहे। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर काफी आश्वस्त हैं, लिहाजा मौजूदा योजनाओं के विस्तार घोषित किए गए हैं। मसलन-70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 'आयुष्मान भारत' के दायरे में रखा जाएगा। ऐसे बुजुर्ग गरीब हों या मध्यवर्गीय हों अथवा सम्पन्न हों, सभी को 5 लाख रुपए तक 'मुफ्त इलाज' की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने 60-70 साल के सभी बुजुर्गों को इस योजना में क्यों नहीं रखा, इसका स्पष्टीकरण सरकार ही दे सकती है। इस आयु-वर्ग को भी कंपनियां 'स्वास्थ्य बीमा' नहीं देती हैं अथवा बीमे की किस्त बहुत महंगी होती है।

यदि सभी वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान' के दायरे में रखा जाता, तो भाजपा एक और लाभार्थी वर्ग तैयार कर सकती थी। भाजपा ने 'समान नागरिक संहिता', 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', 'नागरिकता संशोधन अधिनियम', '3 करोड़ लखपति दीदी' आदि योजनाओं को लागू करने या विस्तार देने की घोषणा की है। भाजपा के वैचारिक कार्यक्रमों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और समान नागरिक संहिता शामिल रहे हैं। अब सिर्फ नागरिक संहिता को ही देश भर में लागू करना शेष है। यह मोदी सरकार के नए कार्यकाल के दौरान सम्पन्न किया जा सकता है। शुक्र है कि 'संकल्प-पत्र' में एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है। भाजपा की वैचारिकता में 'तीन तलाक का कानून' और नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत विदेशों में पीड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों को भारत की नागरिकता देना प्रधानमंत्री मोदी ने शामिल किया था। इससे औसतन 18-20 फीसदी मुस्लिम वोट भी भाजपा के पक्ष में आने लगे हैं। 'संकल्प-पत्र' में गरीबों के लिए 3 करोड़ और पक्के घर बनाना, जबकि 4 करोड़ बनाए जा चुके हैं, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करना, गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाना, 6000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि आदि पुरानी योजनाएं ही हैं, जिनमें विस्तार किया गया है अथवा यथावत जारी रखा गया है।

इन विस्तारों की घोषणा 'अंतरिम बजट' में और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय संबोधन में भी की जा चुकी है। एक योजना में कुछ नयापन प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि आगामी 5 साल तीन तरह के बुनियादी ढांचे पर फोकस किया जाएगा-सोशल, डिजिटल और फिजिकल। सोशल में नए संस्थान, मेडिकल कॉलेज, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कॉलेज, ट्रक चालकों के लिए राजमार्गों पर आरामगाह बनाए जाएंगे। डिजिटल में 5-जी विस्तार और 6-जी पर काम, इंडस्ट्री के लिए 4.0 आधारभूत ढांचे पर काम किया जाएगा। फिजिकल में राजमार्ग, रेलवे, एयरवे, वाटरवे आदि को आधुनिकतम बनाएंगे। 'संकल्प-पत्र' के 78 पन्नों में 24 गारंटियों के साथ 292 वायदे किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी आदि का उल्लेख ही नहीं है। दरअसल मोदी सरकार के 10 सालों में ये दोनों मुद्दे नियंत्रण में रखने की कोशिशें हुई हैं।

राय

हिमाचल में लौटा पोलिथीन

बहुत वर्ष नहीं हुए जब तत्कालीन धूमल सरकार ने देश के पहले हिमालयी राज्य को पॉलिथीन मुक्त करने का बीड़ा उठाया और इस क्रांतिकारी कदम ने एक इतिहास लिख दिया, लेकिन इस व्यवस्था की बाद की सरकारें रक्षा न कर सकीं। पड़ोसी राज्यों की संगत में धीरे-धीरे लौट आया पॉलिथीन, क्योंकि पहाड़ के नियम तो सरकारें बदलते ही दफन हो जाते हैं। सर्वप्रथम जनता ही इनका शिकार करती है, जबकि प्रशासन को अब ऐसे कार्यों की फुर्सत ही कहां। आश्चर्य यह कि इस बीच स्वच्छता अभियान चले। गांव-गांव में सांसदों के नाम पर डस्टबिन लग गए, लेकिन कचरा और नजदीक तथा पॉलिथीन जमीन में धंस गया। हिमाचल ने पॉलिथीन यानी प्लास्टिक की बरसात देखनी हो, तो गांव से शहर तक की करतूत के हादसे किसी भी खड्ड, नदी या जलस्रोत के करीब देखिए। एक व्याख्या तो साल में राष्ट्रीय स्वच्छता का सर्वेक्षण कर देता है और ताज्जुब यह कि शिमला जैसा शहर भी हमने गंदगी की घुटनों तक पहुंचा दिया। आलम यह कि अश्विनी खड्ड के मुहाने तरस गए कि शिमला खुद को संभाल लेगा। यह हर शहर की दास्तान है, जहां वर्षों से कूड़े में प्लास्टिक लद रहा है। शहरों के साथ बहती खड्डें व नदियां बदनाम हैं और यही आगे चलकर हर बांध में तैरती जुबान है। हम जिसे सिल्ट कहते, उसके भीतर हर साल जमा हो रहा है हमारे फर्ज का कूड़ा। कितना मासूम है हिमाचल का प्रशासन।

अब तो सचिवालय को मालूम नहीं होता कि बाहर शिमला में आती-जाती सडक़ों का स्थायी बाशिंदा पॉलिथीन है। किसी ने चलती गाड़ी से फेंका, किसी ने चाकलेट डे मनाया, तो प्लास्टिक भी खुली हवा में चल गया। हर पर्यटक स्थल और बड़े शहरों में आ गई खाने की कोई न कोई चेन। अच्छी पैकिंग में बिकते व्यंजन और साथ में मुफ्त का कोल्ड ड्रिंक जब खत्म होता है, तो शहर की नालियां बताती हैं कि पर्यटन से प्लास्टिक का कितना भयानक रिश्ता है। दूध की थैलियां, ब्रेड के पैकेट और सब्जी की दुकानदारी में शरीक पॉलिथीन अब हमारे परिवेश से पुनः गलबहियां कर रहा है। सवाल नागरिक स्वच्छता से सामुदायिक व्यवहार तक आपत्तियां दर्ज कर रहा है, तो कौन भविष्य के प्रश्नों पर उत्तर खोजेगा। पॉलिथीन हमारी व्यवस्था से इस कद्र चस्पां है कि सरकारी कार्यालय भी ऐसी चुनौती के पर्याय बने हुए हैं। उदाहरण के लिए धर्मशाला स्थित जिलाधीश कार्यालय का पार्किंग हिमाचल का सबसे बड़ा पॉलिथीन स्टोर व आवारा पशुओं द्वारा फैलाई गई गंदगी का खजाना बना हुआ है।

आश्चर्य यह कि पांच कदम पर जिलाधीश सारे जिला को पॉलिथीन मुक्त और स्वच्छता का संदेश दे कर भी यह नहीं देख पाते कि अंततः हो क्या रहा है। कहने को हिमाचल में पांच नगर निगम और पचास के करीब शहरी निकाय हैं, लेकिन इनकी बाहों में फैले पॉलिथीन एक विरासत की तरह टस से मस नहीं होता। शहरों की औकात में इतना दम नहीं कि ढंग से इसका निपटारा कर सकें। यूं तो सरकारें पॉलिथीन खरीद से सडक़ निर्माण तक इसका निपटारा करने की डींगें हांकती रही हैं, लेकिन आफत की यह पुडिया हर जगह और हर वक्त उपलब्ध है। ऐसे में फिर से एक बड़े अभियान के माध्यम से इसे हटाने की नहीं, बल्कि इसकी आदत व जरूरत मिटाने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे। पांच करोड़ पर्यटकों के लक्ष्य में नीतियां, संदर्भ और अधोसंरचना को अगर पुख्ता करने के प्रयास हो रहे हैं, तो सरकार यह व्यवस्था भी करे कि सैलानियों के आगमन से पॉलिथीन का साम्राज्य न बढ़ जाए। कूड़ा कर्कट प्रबंधन की ऐसी तस्वीर जरूरी है जहां प्लास्टिक का कचरा हमारी गतिशीलता का अपशगुन न बन जाए।

सहकारी बैंक जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित नहीं

डा. अश्वनी महाजन

डिपाजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट में सरकार ने जो बदलाव किया है, उसमें जमाकर्ता को बैंक डूबने की स्थिति में बहुत बड़ी राहत मिली है'...

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अधिसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक आते हैं। संविधान में बैंकिंग संघीय सूची में आने वाला विषय है। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुई। इसका उद्देश्य किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्गों के लोगों के विकास में मदद करने तथा बचत को प्रोत्साहन देने का था। देश के सहकारी ढांचे का विस्तार और विकास छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। सहकारी बैंक एवं समितियां शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं। सहकारी बैंक, सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) 1955 द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई की इन पर निगरानी रहती है। सहकारी समितियों पर उनके सदस्यों का स्वामित्व होता है।

इनका नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। ये सहकारी संस्थाएं हैं और इनको सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन संचालित किया जाता है। आरबीआई के दिशा-निर्देश इन पर लागू नहीं होते। ये आम नागरिकों को साहूकारों और बिचौलियों से मुक्त करते हैं। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर ऋण देती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों को अच्छी सेवाएं देना है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं ने ही देश के गांवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोडक़र अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी वित्तीय संस्थाओं के संचालन में कमियों के कारण ये ग्रामीण लोगों के लिए इतनी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुईं। ये छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहीं। बहुत से लोग अभी भी इनके साथ जुड़ नहीं पाए, जिसके कारण हैं : ऋण हेतु निश्चित सुरक्षा प्रदान करने में लोगों की अक्षमता, भूमि रिकॉर्ड का कुप्रबंधन, ऋण चुकाने में सदस्यों की अयोग्यता, पेशेवर प्रबंधन की कमी, नियंत्रण की समस्या आदि। देश के सभी राज्यों में सहकारी बैंकों एवं समितियों में आम तौर पर घोटाले होते रहते हैं। इन घोटालों के कारण हैं : राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रबंधन में अक्षमता, रेगुलर ऑडिट का अभाव, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच का अभाव, बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही घोटाले, गलत तरीके से ऋण देना, बैंक सदस्यों को सीमा से अधिक तथा लंबी अबधि के ऋण देना तथा डिफाल्टर को दोबारा ऋण देना आदि।

देश में सहकारी बैंकों के बड़े घोटालों में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक भी था। इस पर कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने उसे अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कार्य न करने का आदेश दिया था तथा साथ में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा भी निर्धारित की थी। इस बैंक की जमा राशि 11617 करोड़ रुपए थी। यह सभी सहकारी बैंकों से बड़ा बैंक था। देश का सबसे बड़ा बैंक जिस प्रकार संकट का सामना कर रहा है, यह देश की सहकारी बैंक की प्रणाली हेतु चिंता का विषय है। अभी हाल ही में हिमाचल के सोलन जिले में एक अर्बन सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कमेटी ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को सीमा से अधिक ऋण दिया। हालांकि ये पहले भी कई बार ऋण न चुकाने के दोषी थे। इससे सहकारी सभा के 2800 जमाकर्ता अपनी जमा पूंजी वापस लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनमें बहुत सी औरतें हैं। एक जमाकर्ता जो सेना से सेवानिवृत्त है, उसने 13 लाख रुपए निवेश किए थे। उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। उसने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन की पूंजी निवेश की थी, उसको वापस लेने की जंग हार गया हूं, हालांकि मैंने 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयां जीती हैं। इस घोटाले का पता ऑडिट में लगा। इसी तरह का घोटाला मंडी के एक अर्बन बैंक में भी हुआ था।

उसमें भी प्रबंधन कमेटी ने नियमों को ताक पर रखकर ऋण जारी किए थे। एक और घोटाला है जिसमें एक सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 250 करोड़ रुपए के घोटाले में पकड़ा था। उसने नियमों का उल्लंघन कर ऋण अपंजीकृत कंपनी को जारी किया था। सहकारी समितियों में तो ये घोटाले आम हैं। सहकारी बैंकों में हो रहे घोटालों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया। सहकारी बैंकों के प्रबंधन, पूंजी, ऑडिट और लिक्विडेशन को आरबीआई के रेगुलेटरी दायरे में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस बिल को लाया है। उन्होंने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के संकट का उल्लेख किया। सहकारी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कई प्रावधानों से छूट थी। परन्तु अब 2020 का बिल सहकारी बैंकों पर वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही लागू होगा। जब सहकारी बैंको एवं समितियों में घोटाला होता है तो जमाकर्ताओं को अपने पैसे के लिए ही इंतजार और तड़पना पड़ता है। इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है ताकि जमाकर्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसके लिए सहकारी बैंक की एवं सहकारी समितियां आरबीआई द्वारा विनियमित एवं शासित होनी चाहिएं। राज्य सरकारें आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करें। सरकार द्वारा पुनःपूंजीकरण के लिए आरबीआई को दी गई राशि का उपयोग, संकट में आए इन सहकारी बैंकों एवं समितियों पर भी करना चाहिए। सहकारी बैंकों एवं समितियों में हो रहे घोटालों को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि इनके ढांचे एवं संचालन में बुनियादी परिवर्तन किए जाएं। डिपाजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (डीआईसीजीसी) एक्ट में सरकार ने जो बदलाव किया है, उसमें जमाकर्ता को बैंक डूबने की स्थिति में बहुत बड़ी राहत मिली है। यही एक्ट सहकारी समितियों पर भी लागू हो। पांच लाख रुपए तक की जमा राशि की जगह पूरी जमा राशि इंश्योरड/सुरक्षित होनी चाहिए। इन उपायों से ही सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों में लोगों का विश्वास बन पाएगा। तभी उनका सही संचालन होगा।

पीए सिद्धार्थ

गोली मार भेजे में

लोकतंत्र की गंदली और दिन पर दिन सूख रही नदी की मौज़ों में घंटों मौज करने के बाद एक चट्टान पर लेटे झुन्नू लाल विटामिन डी का आनन्द उठा रहे थे। हफ्ते के छः दिन, एक कारख़ाने में बारह घंटे, आठ हजार रुपये की मज़दूरी करने वाले झुन्नू को आज रविवार की छुट्टी थी। देश में मौज पूरी तरह उतरी नहीं थी। लोकतंत्र की नदी में अभी कुछ जीवन शेष था। नहीं तो हो सकता था कि वह हफ्ते के सातों दिन कारख़ाने में मौज मारने के आदी हो जाते। कई दिनों से घर के सरकारी नल में पानी, बरसों से महंगाई से मिली राहत की तरह ग़ायब था। महंगाई से राहत न मिलने पर आदमी सालों किसी तरह जी लेता है। लेकिन बिना नहाए कितने दिन रह सकता है। मजबूरन, नहाने के लिए मुझे नदी पर जाना पड़ा। झुन्नू को देखते ही मैं चहक उठा। लगा कि कोई तो अपना है। सोचा कि लोकतंत्र की नदी में गहरे उतरते हुए पांव फिसलने पर कोई तो बचाने वाला होगा। नहीं तो डूबने वाले कितने लोग जमानत को तरस रहे हैं। झुन्नू के पास पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। औंधे लेटे हुए अपने साथ लिटाए मगरमच्छ के बच्चे को थपकी देकर सुला रहे थे। मैंने नोट किया कि उनका सिर पारदर्शी लग रहा है। पूछा तो कहने लगे कि समाज में कुतर्क इतना बढ़ गया है कि भेजा निकाल कर घर की अलमारी में बंद कर दिया है। लेकिन ताला अलीगढिया नहीं, गोदरेज का लगाया है। हो सकता है कि अलीगढ़ का ताला विधर्मी निकले। फिर गाने लगे, 'गोली मार भेजे में, ढिचकियाऊं कि भेजा शोर करता है।' उनके साथ-साथ मगरमच्छ का बच्चा भी अपने पंजे से ताल देने लगा।

लेकिन मेरी उत्सुकता शांत नहीं हुई। मैंने उनसे अनुनय करते हुए भेजा निकालने की वजह पूछी तो वह पालथी मार कर बैठ गए। मगरमच्छ के बच्चे को अपनी गोद में लेकर सहलाते हुए गाने लगे, 'मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है?' फिर आंखें बंद करके किसी गहरे में उतरते हुए बोले, 'सिर में गोबर भरने से बेहतर है कि दिमाग़ निकाल कर अलमारी में रख दो। कम से कम सार्वजनिक जीवन में कुतर्क तो नहीं झेलने पड़ेंगे। अगर कोई सिर में गोली भी मारेगा तो आरपार हो जाएगी। नहीं तो सिर में गोबर होने पर गोली बीच में फंस सकती है। ऐसे में कोमा में जाने की पूरी संभावना है। कुतर्कों को देखकर भेजा शोर किए बिना रह नहीं सकता। बच्चे अभी छोटे हैं और बीवी ज़वान। फिर मुझ में देश सेवा का वह जज़्बा भी नहीं कि उन्हें छोड़ कर घर से भाग जाऊं। बाबू! तर्क के सहारे लडऩे पर मन तो मारा जा सकता है। लेकिन पेट कौन मारेगा? अढ़ाई फुट का यह गड्ढा तो खाना माँगता है, मुसलसल। अपने बौद्धिक विलास के लिए मैं अपने परिवार को ख़त्म नहीं कर सकता। पर यह समझ नहीं आता कि आदमी मगरमच्छ हो गया है या मगरमच्छ आदमी। लेकिन देखो! दोनों में कितना प्रेम बढ़ गया है। मेरी गोद में यह मगरमच्छु कितना पुरसुकूं महसूस कर रहा है। कोमा में जाने से बेहतर है कि आदमी ज़ोम्बी बन कर जीता रहे। फिर चाहे भेजा निकाल कर जिए या गोबर भर कर। कम से कम परिवार का साथ तो बना रहेगा।

हां, भेजा निकालने का इतना फायदा अवश्य होता है कि आदमी कुतर्कों में नहीं जीता। दिमाग़ में गोबर होने पर आदमी कुतर्की हो जाता है।' उनके जवाब से मुत्तासिर होते मैंने उनसे भेजे को तिलांजलि देने की असली वजह जाननी चाही तो बोले कि जिस समाज में चुनावों में खड़े उम्मीदवार कुतर्कों के सहारे अपने आपको सही ठहराते हुए अपना चुनाव प्रचार करें और उनके समर्थक भी उनके पक्ष में मतदान करें, उसके पतन को कौन रोक सकता है। उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद, मैं उनकी गोद से मगरमच्छु को अपनी बांहों में लिए, बिना कुछ देखे और सोचे-समझे लोकतंत्र की नदी में नहाने के लिए कूद पड़ा।

अब पार्टी करने वालों की होगी मौज, एक साथ 50 लोगों का खाना डिलीवर करेगी Zomato

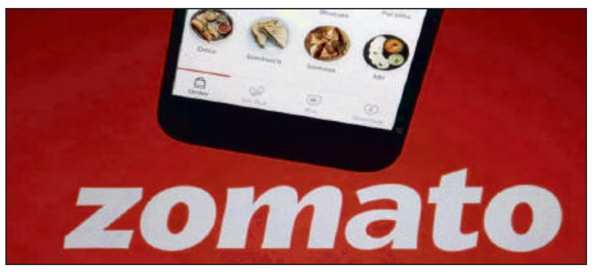

परिवहन विशेष न्यूज

फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमैटो ने एक लार्ज ऑर्डर फ्लीट पेश किया है। जोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने बताया कि यह पार्टी जैसे इवेंट में एक साथ अधिकतम 50 लोगों का खाना डिलीवर करेगा। इससे ग्राहकों को बड़ा ऑर्डर देने में सहूलियत होगी। जोमैटो अभी अपने इस फ्लीट में टेंपरेचर कंट्रोल जैसी कई सुविधाएं जोड़कर और बेहतर बनाएगा।

नई दिल्ली। अगर आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शादी या फिर जन्मदिन के मौके पर बड़ी पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन खाना बनाने की समस्या है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने मंगलवार को अपना पहला लार्ज ऑर्डर फ्लीट (Large Order Fleet) पेश किया है। यह पार्टी जैसे ग्रुप इवेंट में एकसाथ अधिकतम 50 लोगों का खाना डिलीवर करेगा।

सीईओ दीपिंदर गोयल ने किया एलान

जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पहले लार्ज फ्लीट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फ्लीट में सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। यह अमूमन बड़े ऑर्डर को ही डिलीवर करेगा। पहले इस तरह के ऑर्डर को रेगुलर फ्लीट डिलीवरी पार्टनर के जरिए पूरा किया जाता था। इस तरह से खाना मंगाने वाले कस्टमर को थोड़ी असुविधा होती थी।

इस फ्लीट को और भी बेहतर करेगी जोमैटो

जोमैटो अपने लार्ज ऑर्डर फ्लीट में अभी कई सुविधाओं को जोड़ेगी। कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कहा कि इस फ्लीट में टेंपरेचर कंट्रोल के साथ कूलिंग कंपार्टमेंट और हॉट बॉक्स जैसी महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी जाएंगी। मतलब कि अगर कोई कस्टमर गर्म या ठंडी चीज ऑर्डर करता है, तो वे उसे गर्म या ठंडी ही मिले। जोमैटो के शेयर की बात करें, तो यह मंगलवार (16 अप्रैल) को 0.85 प्रतिशत गिरकर 186.70 रुपये पर बंद हुआ।

लिंकेडीन पर टॉप कंपनियों में शामिल है ये बड़े नाम

परिवहन विशेष न्यूज

प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने मंगलवार को भारत के लिए 2024 टॉप कंपनियों की लिस्ट जारी की जिसमें आईटी कंपनियों ने टॉप तीन रैंक हासिल की जबकि वित्तीय सेवा फर्मों ने इस क्षेत्र की 25 कंपनियों में से 9 के साथ सूची में अपना दबदबा बनाया। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे आगे है इसके बाद एक्सेंचर और कॉग्निजेंट दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

नई दिल्ली। भारत में काम करने के लिए टॉप कंपनियों की लिंक्डइन की लेटेस्ट लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे आगे है, इसके बाद एक्सेंचर और कॉग्निजेंट दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने मंगलवार को भारत के लिए 2024 टॉप कंपनियों की लिस्ट जारी की, जिसमें आईटी कंपनियों ने टॉप तीन रैंक हासिल की, जबकि वित्तीय सेवा फर्मों ने इस क्षेत्र की 25 कंपनियों में से 9 के साथ सूची में अपना दबदबा बनाया।

8वें वर्जन में लिंक्डइन डेटा से इनसाइट दी गई है, और टॉप 25 बड़ी कंपनियों, 15 सर्वश्रेष्ठ मध्यम आकार की कंपनियों को लिस्ट किया गया है। इन कंपनियों के भीतर मांग वाले कौशल, टॉप स्थानों और सबसे बड़े नौकरी कार्यों पर इनसाइट दी गई है।

टॉप पर रहा TCS

इन बड़ी कंपनियों के बीच, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस साल अपनी टॉप पॉजिशन को बरकरार रखा, उसके बाद एक्सेंचर और कॉग्निजेंट का स्थान रहा।

लिंक्डइन ने कहा कि पिछले साल के रुझान को जारी रखते हुए, मैक्वेरी ग्रुप (चौथे स्थान), मॉर्गन स्टेनली (पांचवें), और जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी (छठे) सहित इस क्षेत्र की 25 में से 9 कंपनियों के साथ वित्तीय सेवाओं ने 2024 की सूची में अपना दबदबा बनाया।

सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (सास) प्लेटफॉर्म लेंट्रा टॉप मीडिल आकार की कंपनियों की सूची में पहले स्थान पर है, इसके बाद भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म मेकमाईट्रिप है।

नाइका और फैंटसी स्पोर्ट्स भी लिस्ट में शामिल

इस सूची में फैशन और ब्यूटी रिटेलर नाइका और फैंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 भी शामिल हैं, जो भारत में नौकरी चाहने वालों के लिए विभिन्न उद्योगों में उपलब्ध अवसरों की पेश करते हैं।

आंकड़ों से पता चला कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में टॉप कंपनियां जिन मांग वाले कौशल की तलाश कर रही हैं उनमें निवेशक संबंध, पूंजी बाजार और निवेश बैंकिंग शामिल हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज तकनीक, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र (एसडीएलसी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे कौशल की तलाश में हैं।

भारत की सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को टॉप पॉजिशन का नाम दिया गया जहां ये टॉप कंपनियां स्थित हैं और प्रतिभाओं को नियुक्त करना चाहती हैं, इसके बाद हैदराबाद, मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और पुणे को स्थान मिले।

दिल्ली का IGI Airport दुनिया के शीर्ष 10 में बरकरार, जानिए कौन-सा है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) वर्ल्ड ने दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत का आईजीआई एयरपोर्ट भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में दस में से पांच एयरपोर्ट अमेरिका के हैं। आईजीआई साल 2022 में इस लिस्ट में 9वें पायदान पर था जो अब 10वें स्थान पर आ गया है।

नई दिल्ली। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) वर्ल्ड ने दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट भी 2023 के टॉप 10 में शामिल है।

ACI World के व्यस्त एयरपोर्ट रैंकिंग में पिछले साल 2022 में आईजीआई की रैंकिंग 9वीं थी। इसके साथ ही 2021 में 13वीं और कोरोनावायरस महामारी से पहले 2019 में इसकी रैंक 17वीं थी।

टॉप 10 में पांच एयरपोर्ट अमेरिका के

ACI ने बताया है कि दिल्ली स्थित आईजीआई एयपोर्ट से सालाना 7.22 करोड़ पैसेंजर यात्रा करते हैं। इस लिस्ट में अमेरिका का हार्ट्सफील्ड-जैकसन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले पायदान पर है, जो सालाना 10.46 करोड़ पैसेंजर को यात्रा करवाता है। इस लिस्ट में अमेरिका के पांच एयरपोर्ट शामिल है। रैंकिंग में सबसे लंबी छलांग हनेडा एयरपोर्ट ने लगाई हैं। साल 2022 में इसकी रैंकिंग 16वीं थी, जो 2023 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

इनसाइड

तगड़े ब्याज के साथ सेफ्टी की गारंटी, इन बैंकों में करा सकते हैं एफडी

बैंक FD (Fixed Deposit) निवेश के सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जाता है। साथ ही इसमें तगड़ा ब्याज भी मिलता है। अगर आप सीनियर सिटिजन हैं तो यह लाभ और भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको बैंक अतिरिक्त ब्याज भी देते हैं।

नई दिल्ली। बैंक FD (Fixed Deposit) निवेश के सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जाता है। साथ ही, इसमें तगड़ा ब्याज भी मिलता है। अगर आप सीनियर सिटिजन हैं, तो यह लाभ और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बैंक अतिरिक्त ब्याज भी देते हैं।

आइए जानते हैं कि कौन से बैंक सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) को एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दे रहे हैं। इन एफडी के साथ अच्छी बात यह है कि इनमें लॉक-इन पीरियड भी ज्यादा नहीं है।

DCB बैंक दे रहा 8.1 प्रतिशत का ब्याज

अगर आप सीनियर सिटिजन और डीसीबी बैंक में 26 महीने से 37 महीनों में मैच्योर होने वाली एफडी कराते हैं, तो आपको 8.1 फीसदी ब्याज मिलेगा।

RBL बैंक में भी एफडी पर मोटा ब्याज

आरबीएल बैंक में भी एफडी कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मोटा ब्याज मिलेगा। हालांकि, उन्होंने 24 महीने से 36 महीने के बीच मैच्योर होने वाली एफडी करानी होगी। इस पर 8 फीसदी ब्याज मिल सकता है।

फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगेगी रोक? निवेशकों को कंगाल होने से बचाने का उपाय कर रही सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

फ्यूचर एंड ऑप्शन (FO Trading) में ट्रेडिंग करने वाले रिटेल इन्वेस्टर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन 10 में से 9 निवेशकों को इसमें भारी नुकसान हो रहा है। कुछ तो अपनी जिंदगीभर की कमाई गंवा बैठ रहे हैं। ऐसे में फाइनेंशियल रेगुलेटर्स मिलकर एक कमेटी बना रहे हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट के जोखिमों का आकलन करेगी और नीतिगत बदलाव का सुझाव देगी।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से डेरिवेटिव्स मार्केट (Derivatives Markets) में निवेश करने का चलन तेजी से बढ़ा है। यहां पर लाखों निवेशक रातोंरात अमीर होने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन अधिकतर अपनी सारी जमा-पूंजी गंवा देते हैं।

यहां तक कि मार्केट रेगुलेटर SEBI का कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O Trading) जैसे डेरिवेटिव्स में कारोबार करने वाले 10 में से 9 निवेशक कंगाल हो जाते हैं। यही वजह है कि कई मार्केट एक्सपर्ट ने इसे जुआ भी करार दिया है।

अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि SEBI और रिजर्व बैंक (RBI) जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर ने डेरिवेटिव्स मार्केट में निवेश के बढ़ते जोखिम का आकलन करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। यह कमेटी निवेशकों को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान पता लगाएगी और अगर जरूरती हुआ, तो नीतिगत बदलाव की सलाह भी देगी।

कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?

पिछले पांच साल के दौरान में ऑप्शन ट्रेडिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। इसमें खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कहना है कि 2023-24 में ऑप्शन ट्रेडिंग की वैल्यू 907.09 ट्रिलियन डॉलर रही, जो एक साल पहले के मुकाबले दोगुने से अधिक है। यही वजह है कि सरकारी संस्थाओं को लगता है कि इसकी बारीकी से निगरानी की जरूरत है।

कमेटी में कौन-कौन शामिल होगा?

डेरिवेटिव्स मार्केट का आकलन करने वाली कमेटी का गठन फाइनेंशियल स्टेबलिटी डेवलपमेंट काउंसिल करेगी। रॉयटर्स के मुताबिक, इसमें वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर और मार्केट रेगुलेटर SEBI शामिल होंगे। इसके मेंबर और रिपोर्टिंग टाइमलाइन के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा।

पर्सनल लोन के इस्तेमाल पर भी नजर

यह कमेटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के संभावित सिस्टैमिटक रिस्क का आकलन करेगी। साथ ही, निवेशकों के हितों की सुरक्षा और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग बढ़ाने के उपाय भी सुझाएगी। यह कमेटी यह भी पता लगाएगी कि कहीं छोटे अनसिक्योर्ड लोन लेने वालों की संख्या में उछाल और ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच कोई संबंध तो नहीं है। मतलब कि लोग पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के पैसों से कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं।

यह आशंका इसलिए भी अधिक है, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों से यह नहीं पूछते कि वे पर्सनल लोन का इस्तेमाल किस काम में करेंगे। रिजर्व बैंक का डेटा बताता है कि पर्सनल लोन की ग्रोथ में सालाना आधार पर 20 प्रतिशत से अधिक उछाल आया है।

RBI फिर एक्शन में, अब मुंबई और यूपी के इन बैंकों पर लगाया प्रतिबंध; खाते से इतने ही पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक

परिवहन विशेष न्यूज

बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर आरबीआई ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ पर कई प्रतिबंध लगाए। इसमें ग्राहकों के लिए मुंबई बैंक से 15000 रुपये और प्रतापगढ़ बैंक से 10000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है। अब बैंक आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी लोन और एडवांस को ग्रांट या रिन्यू नहीं कर सकता है।

नई दिल्ली। आरबीआई ने सोमवार को नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें लोनदाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स के लिए 10,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है।

इसके साथ ही बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर आरबीआई ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है।

जमाकर्ता केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने के हकदार होंगे।

ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत निर्देशों के रूप में प्रतिबंध सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार की समाप्ति से लागू होते हैं।

लगे हैं ये प्रतिबंध

अब, बैंक आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी लोन और एडवांस को ग्रांट या रिन्यू नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई दायित्व नहीं ले सकता है, या अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में कोई भुगतान नहीं कर सकता है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 10,000(सर्वोदय बैंक मुम्बई से 15000 रुपये) रुपये से अधिक की राशि को आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों में बताई गई शर्तों के अधीन निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इजरायल पर हमले का बदला लेगा अमेरिका! क्या ईरान के तेल निर्यात पर बैन लगाएंगे जो बाइडेन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने से दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इससे कई लोगों का मानना है कि इजरायल का दोस्त होने के नाते अमेरिका का जो बाइडेन (Joe Biden) प्रशासन ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगा सकता है।

अमेरिका में उठ रही ईरान पर बैन की मांग

अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी लगातार जो बाइडन प्रशासन पर दबाव बना रही है कि वह इजरायल पर हमले के बाद ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाएं। ड्रॉनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि वह ईरान पर बैन लगाने के लिए बिल लाएगी। उसका आरोप है कि बाइडन प्रशासन ने पाबंदियों में ढील देकर ईरान के लिए तेल बेचना आसान कर दिया है, जिससे 'आतंकियों को पाला पोसा' जा रहा है।

हालांकि, इन सबके बावजूद इस बात की गुंजाइश काफी कम है कि जो बाइडन प्रशासन ईरान पर कोई सख्त प्रतिबंध लगाएगा।

ईरान पर पाबंदी लगाने से क्यों बच रहे बाइडेन?

अमेरिका में जल्द चुनाव होने वाले हैं। अगर ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगता है, तो इससे बाकी दुनिया के साथ अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व महंगाई बढ़ने के डर से ही ब्याज दरों में कटौती करने से बच रहा है। ऐसे में जो बाइडेन चुनावी सीजन में महंगाई बढ़ाने जैसा बड़ा जोखिम शायद ही लेना चाहेंगे।

ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है। पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के संबंध काफी खराब हो गए थे। दोनों के दरम्यान लंबे समय तक ट्रेड वॉर (Trade War) भी चला। अब अमेरिका और चीन के संबंध कुछ सुधरे हैं और जो बाइडेन प्रशासन बेवजह चीन को नाराज नहीं करना नहीं चाहेगा।

सरकार ने फिक्स्ड डिपॉजिट से अर्जित ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों से एकत्र किए 27 हजार करोड़ रुपये

एसबीआई के रिसर्चर्स ने कहा कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर 27000 करोड़ रुपये से अधिक कर वसूले हैं। एसबीआई शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में जमा की कुल राशि 143 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के अंत में 14 लाख करोड़ रुपये से 34 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े लोनदाता एसबीआई के रिसर्चर्स ने कहा कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर 27,000 करोड़ रुपये से अधिक कर वसूले हैं। एसबीआई शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में जमा की कुल राशि 143 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024 के अंत में 14 लाख करोड़ रुपये से 34 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च ब्याज दरों के कारण वरिष्ठ नागरिकों के बीच सावधि जमा(Fixed Deposit) में निवेश करने में रुचि बढ़ी है, क्योंकि इसी अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की कुल संख्या 81 प्रतिशत बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई है।

वरिष्ठ नागरिकों से मिला सबसे ज्यादा ब्याज

शोधकर्ताओं की मानें तो इनमें से कम से कम 7.3 करोड़ अकाउंट में 15 लाख रुपये से अधिक की राशि है। यह मानते हुए कि जमा पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है, वरिष्ठ नागरिकों ने अकेले ब्याज के रूप में वित्त वर्ष 24 में 2.7 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बैंक जमा से 2.57 लाख करोड़ रुपये और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से शेष शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए 10 प्रतिशत (औसत) कर को सभी वर्गों के बीच सुसंगत मानते हुए, भारत सरकार द्वारा कर संग्रहण लगभग 27,106 करोड़ रुपये होगा।

इसमें कहा गया है कि वृद्धिशील सावधि जमा में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी पांच साल पहले के 15 प्रतिशत से बढ़कर अब 30 प्रतिशत हो गई है।

TDS की सीमा में बढ़ोतरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि जमा दरों में वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च ब्याज दर अंतर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जमा योजनाओं ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा अभिवृद्धि में एक विवर्तनिक बदलाव को प्रेरित किया है।

इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का सरकार का कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में काम कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तरलता की उतार-चढ़ाव वाली बाधाओं के बीच कुछ बैंक जमा राशि को लुभाने में आक्रामक रहे हैं, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली ने फरवरी 2023 से आरबीआई द्वारा दर बनाए रखने के बावजूद वित्त वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में जमा दर बढ़ा दी है।

जमाकर्ताओं के व्यवहार में 'स्पष्ट बदलाव' मूल और सावधि जमा के बीच ब्याज दर के अंतर को भुनाने की प्रवृत्ति है, सावधि जमा की वृद्धिशील हिस्सेदारी 93 प्रतिशत तक बढ़ रही है और कम लागत वाले चालू और बचत खातों की हिस्सेदारी घट रही है।

मोदी ने महिलाओं को केंद्रित रखते हुए सभी विकास योजनाए लागू कराई : रक्षा भंडारी

पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी और आपके एक वोट के कारण हो रहा है

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ भाजपा महिला मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन आज भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा कि प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी संभाग प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी मंडावत, महिला मोर्चा जिला प्रभारी सिंपल वैष्णव, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, जिलाध्यक्ष मंजू पालीवाल, जिला संयोजक मंजू चेचानी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ,भीलवाड़ा लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, रेखा परिहार अध्यक्ष नगर पालिका हमीरगढ़, शिवांगी कानावत युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, मीरा कराड प्रदेश एसटी मोर्चा कार्य समिति सदस्य के आथित्य में संपन्न हुआ प्रारंभ में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया।

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को केंद्रित करते हुए सभी विकास योजनाएं बनाई गई है जिससे 70% योजनाओं का लाभ महिलाएओ ने उठाया है पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके एक वोट के कारण हो रहा है आपका वोट की ताकत से देश को मजबूत सरकार दी और सरकार देश हित में मजबूत कदम उठा रही हैं ।

भंडारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की मोदी सरकार एवं प्रदेश की भजनलाल सरकार महिलाओं के आर्थिक शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है उन्होंने महिला मोर्चा के विविध छोटे-छोटे कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता से जुड़ने को कहा, सभी महिलाएं एकजुट होकर अपने को भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल मानकर भाजपा को वोट दिलाएभाजपा जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी में जानकारी देते हुए बताया कि महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए संभाग प्रभारी पिंकी मंडावत में तीन तलाक तथा महिलाओं की आत्म सम्मान के लिए शौचालय निर्माण, धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना जैसी अनेक महिला कल्याणकारी महिलाओ के हित निर्णय लिए हैं।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने 50% आबादी नारी शक्ति वंदन कानून संसद के उद्घाटन के समय नारी को शक्ति मानते हुए 33% आरक्षण विधानसभा व लोकसभा में दिया है मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए तीन तलाक का कानून लागू कराया है उन्होंने महिलाओं से आहान किया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में कराये लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह ने कहा कि महिला मोर्चा राजस्थान का सबसे सशक्त मोर्चा है उन्होंने कहा कि पद के पीछे भागेंगे तो पद दुर जाएगा और काम के पीछे भागेंगे तो पद आपके पास आएगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान है एवं लोकतंत्र की जननी बुथ होता है महिलाए अपनी पूरी ताकत से 80% से ज्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान कराये महिला सम्मेलन में पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ,रेखा पूरी, नाथी देवी कुमावत एवं आरती कोगटा भी मंचासीन थी।

सम्मेलन में सुमित्रा पोरवाल, सुलक्षणा शर्मा, मीनाक्षी नाथ, सीमा सोनी, नेहा नागर ,ज्योति आशीर्वाद, ईन्दू टॉक ईन्दू बंसल ,रेखा पुरी संगीता त्रिपाठी, रेखा शर्मा, सुनीता गुप्ता, रजनी जैन, नैना व्यास ,रोमा लखवानी शारदा आचार्य, अनुराधा कंवर, डिंपल ईनाणी, चंदा सोनी, कल्पना तिवारी, सुशीला डाड ,मोना डाड लीला साहू, ज्योति यादव संपत्ति रावत, प्रेम जाट, सोनिया गहलोत, संगीता अग्रवाल, पिंकी शर्मा, दीपा सोनी, कल्पना तिवारीसम्मेलन में उपस्थित थी।

महिला मोर्चा सम्मेलन का अंत में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं महिला मोर्चा संयोजक मंजू चेचानी ने आभार व्यक्त किया।

अगले साल दलित जस्टिस बीआर गवई बनेंगे सीजेआई, बोले वजह सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड है। अगले साल इस पद पर जस्टिस भूषण रामकृष्ण - गवई यानी बीआर गवई आसीन होगे। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम में लेक्चर के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने खुलासा किया कि उनके जैसा व्यक्ति इस पद तक पहुंच सकता है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉ.भीम राव आम्बेडकर हैं। उन्होने यह भी कहा कि वह सिर्फ डॉ. आम्बेडकर की वजह से ही जज बन पाए। बता दें कि जस्टिस गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे ऐसे शख्स होगें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेगे। सोमवार को आंबेडकर मेमोरियल लेक्चर के दौरान अपनी बात रखते हुए जस्टिस गवई ने कहा 'भारत के संविधान का श्रेय डॉ. भीम राव आंबेडकर को जाता है ।सिर्फ उन्ही की वजह से मेरे जैसा इंसान इस पद तक पहुंच सका ।मैने झुग्गी- बस्ती वाले सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है ।अपने इस भाषण में जस्टिस गवई ने संविधान के अनुच्छेद-32 का भी खूब जिक्र किया जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 80 हजार केस पेंडिंग है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस गवई साल 2019 में जज बने। 2003 से 2019 तक यानी 16 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हैं ।साल-1985 में वकील बने। जस्टिस बीआर गवई लंबे समय तक बाम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में वकालत की प्रेक्टिस करते रहे ।पहले वह सरकारी वकील बने ।और बाद में हाई कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस गवई के पिता आरएस गवई ने भीम राव आंबेडकर के साथ काम किया था। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) की स्थापना भी की थी।

चारभुजा को 56 षठरस व्यंजनों का लगेगा भोग रामनवमी 17 को

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा । श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बडा मंदिर में चैत्र रामनवमी के विशेष पर्व के अवसर पर चारभुजा नाथ को षठरस व्यंजनों का छप्पन भोग लगेगा । ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस बार रामनवमी के विशेष आयोजन पर षठरस व्यंजनों द्वारा तैयार जिसमें मीठा, खट्टा, कसेला, कड़वा,खारा व नमकीन 6 प्रकार के व्यंजनों का छप्पन भोग इंजीनियर ओम प्रकाश हिंगड़ एवं परिवार जनों की ओर से लगाया जाएगा।

भीलवाड़ा में रोजगार मोदी की गारंटी वादा खिलाफी कांग्रेस की फितरत में : अग्रवाल

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाडा। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल आज शाहपुरा विधानसभा के दौरे पर रहे। जहां उन्होंने कई सभाओ को सम्बोधित करते हुये कांग्रेस को आड़े हाथो लेते हुये कांग्रेस की वादा खिलाफी फितरत को आमजन के बीच रखा ।लोकसभा मीडिया प्रभारी विनोद झुर्रानी ने बताया कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने शाहपुरा विधानसभा की सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि भीलवाड़ा में रोजगार देना मोदी की गारंटी है। अग्रवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथो लेते हुये कहा कि वादा खिलाफ कांग्रेस की फितरत में है। पूर्व में भी किसानों के कर्ज माफी में कांग्रेस द्वारा वादा खिलाफी की गई थी। भीलवाड़ा को मेमू कोच के सपने दिखाये जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व तक नहीं है। आज पुनः कांग्रेस प्रत्याशी एक नया झूमला 1 लाख नौकरी का लेकर आये है। भीलवाड़ा की इतनी ही चिंता थी तो 15 साल कहा थे। अग्रवाल ने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी चम्बल परियोजना के लिये एन.ओ.सी. क्यों नहीं लाये, एक फिट पाईप लाईन भी स्वीकृत नहीं करवाये पाये और चम्बल परियोजना का श्रेय ले रहे है।

लोकसभा प्रत्याशी ने शाहपुरा विधानसभा की रूपाहेली, कुंडिया कलां, कासोरिया, डाबला, घरटा, समेलिया, माताजी का खेड़ा, रहड़, बच्छ खेड़ा, लसाड़यि, मुहला, आमली कलां, कादिसहना, शाहपुरा में सभाओं का आयोजन कर आमजन से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की व सघन जन सम्पर्क किया।

जन सम्पर्क के दौरान विधायक लालाराम बैरवा, प्रधान विजेन्द्र सिंह, लक्ष्मलाल सोनी, राजेन्द्र सिंह खामोर, परमेश्वर पारीक, गोपाल चरण सिसोदिया, अशोक चेचाणी, बजरंग सिंह राणावत, अविनाश जीनगर, नंदलाल गुर्जर, सरपंच चांदमल पारीक, सुवालाल गुर्जर, सांवरमल सेन, परमेश्वर बलाई, गणेश जाट, सुरेश शर्मा, श्यामलाल, जयराज सिंह बल्दरखा, शिव जाट, कैलाश सुवालका, ओम पाराशर, शिव टेलर, शिव कुमावत, नंदकिशोर बैरवा, हनुमान सिंह राणावत, प्रद्युमन सिंह सहित सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कल दिनांक 17अप्रैल को भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा शहर के दौरे पर रहेगे। जहां सुबह ग्रोथ सेन्टर, दोपहर में न्यू क्लॉथ मार्केट एवं सांयकाल रिको ऐरियो एवं शास्त्री मण्डल के सालासर बालाजी मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेगें।

इस महीने पूरा होगा केजीपी-अलीगढ़ रोड इंटरचेंज का काम, जाम और प्रदूषण से मिलेगी निजात

एमपी-केजीपी एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद से ही पलवल शहर में जाम को कम को कम करने के लिए पलवल-अलीगढ़ रोड पर इंटरचेंज बनाए जाने की मांग उठ रही थी। इस पत्र में केजीपी एक्सप्रेस वे को पलवल-अलीगढ़ रोड से जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहित करने के आदेश दिए गए थे। इससे देवर एयरपोर्ट जाने वालों को भी फायदा होगा।

पलवल। कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) एक्सप्रेस-वे से पलवल-अलीगढ़ रोड को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण कार्य इस माह पूरा हो जाएगा। इंटरचेंज का निर्माण कार्य करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है। इसका निर्माण पूरा होते ही इसे ट्रायल के लिए खोल दिया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट जाने वालों को होगा फायदा : इंटरचेंज के बनने से जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य स्थानों के लिए जाने वाले वाहनों को शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। पलवल शहर को जाम व प्रदूषण से राहत मिलेगी। केएमपी-केजीपी एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद से ही पलवल शहर में जाम को कम को कम करने के लिए पलवल-अलीगढ़ रोड पर इंटरचेंज बनाए जाने की मांग उठ रही थी। क्षेत्रवासियों की इस मांग को देखते हुए इंटरचेंज को मंजूरी दी गई थी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को पलवल जिला उपायुक्त को पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में केजीपी एक्सप्रेस वे को पलवल-अलीगढ़ रोड से जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहित करने के आदेश दिए गए थे। वर्ष 2021 में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केजीपी एक्सप्रेस वे को पलवल-अलीगढ़ रोड से जोड़ने के लिए 65 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

इसके बाद पिछले साल केजीपी एक्सप्रेस-वे से पलवल-अलीगढ़ रोड को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब इस इंटरचेंज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। हालांकि इसका निर्माण कार्य फरवरी माह में ही पूरा करने की तैयारी थी। मगर निर्माण कार्य फरवरी माह में पूरा नहीं हो पाया था।

जाम और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति : रोजाना पलवल-अलीगढ़ रोड से आठ हजार से ज्यादा वाहन आवागमन करते हैं। इनमे भारी वाहनों की संख्या अत्यधिक है। अभी इन वाहनों को शहर से होते हुए गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति पैदा होती है और प्रदूषण भी फैलता है। इंटरचेंज के शुरू हो जाने से शहर में जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी।

अलीगढ़ से आने वाले वाहन शहर में दाखिल होने की बजाय सीधे इस इंटरचेंज का उपयोग कर केजीपी-केएमपी एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पहुंच सकेंगे। आगरा, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी समेत अन्य हिस्सों से आने वाले वाहन बिना शहर में दाखिल हुए गांव अटोहां में केजीपी से होते हुए इस इंटरचेंज का उपयोग कर अलीगढ़ जा सकेंगे। यह इंटरचेंज जेवर एयरपोर्ट से आवागमन की राह को भी आसान बनाएगा। इसी के साथ इंटरचेंज के बनने से व्यवसायिक रूप से भी क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। अलीगढ़ रोड पर पड़ने वाले गांवों को भी इसका विशेष रूप से फायदा होगा। पेलक, ताराका, घोड़ी, चांदहट, सिहौल, मीसा, गुरवाड़ी, किठवाड़ी, बड़ौली, खजूरका, बड़ोली, राजपुर खादर समेत दर्जनों गांव सीधे केजीपी एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएंगे।

वेदवन की तर्ज पर अब ग्रेटर नोएडा में बनेगा आयुर्वेद पार्क, जड़ी-बूटियों से इलाज की मिलेगी जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा के वेदवन पार्क की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आयुर्वेद पार्क विकसित होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण के मुताबिक इस पर मसौदा तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद इस पर कार्य शुरू होगा। पार्क में लोगों को आयुर्वेद का इतिहास उसके महत्व आयुर्वेदिक इलाज की जानकारी के साथ ऐसे पेड़-पौधों की जानकारी मिलेगी।

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए नोएडा के वेदवन पार्क की तर्ज पर आयुर्वेद पार्क विकसित होगा। लोकसभा चुनाव के बाद सलाहकार कंपनी इसे विकसित करेगी। पार्क 15 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। इसके लिए भूमि चिह्नित है।

नोएडा के सेक्टर 78 में वेदवन पार्क 12 एकड़ में विकसित है। सैलानियों के लिए ये प्रमुख स्थान है। इस पार्क में वेदों व पुराण की जानकारी दी गई है। कलाकृतियां, वाटर फाल आदि में झलक दिखती है। ग्रेटर नोएडा के लोग भी ऐसे पार्क की मांग कर रहे थे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस मांग पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आयुर्वेद पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इस पार्क में आयुर्वेद का इतिहास, उसके महत्व, आयुर्वेदिक इलाज संग ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाएंगे जो अच्छे सेहत के लिए बेहद अहम हैं।

नोएडा का अनोखा पार्कः रोजाना लेजर शो से मिलेगा वेदों का ज्ञान, जानिए टिकट से लेकर इससे जुड़ी खास बातें

चुनाव के बाद शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया

जड़ी-बूटियों की जानकारी व उससे होने वाले इलाज की जानकारी दी जाएगी। प्राधिकरण के मुताबिक इस पर मसौदा तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद इस पर कार्य शुरू होगा। टेंडर आदि की प्रक्रिया भी चुनाव के बाद शुरू होगी।

सिटी पार्क के गलियारों में गूंजेगा संगीत

ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क को और आकर्षित बनाने की भी प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्क में लगे पेड़-पौधों को रोशनी से जगमग करने को उन पर रंग-बिरंगी लाइट लगेगी। फुटपाथ के दोनों ओर भी रंग-बिरंगी रोशनी संग धुन बजेगी।

पिछले दिनों प्राधिकरण ने इसके लिए कंपनियों से सुझाव मांगे थे। सुझाव मिल गए हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव बाद सौंदर्यीकरण का कार्य होगा।

लैब टेक्नीशियन लैब एवं चिकित्सा जगत के मजबूत स्तंभ होते हैं :- डाँक्टर वर्षा सिंह

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। महात्मा गांधी अस्पताल के सेंट्रल हॉल में माइक्रोस्कोप के आधार रखने वाले जकारिया जेनसन की याद में 15 अप्रैल को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया गया।

लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर ने जानकारी देकर बताया की 15 अप्रैल सोमवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय में आयोजित हुए लैब टेक्नीशियन दिवस समारौह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा डाँक्टर वर्षा सिंह ने की वही मुख्य अतिथि चिकित्सा अधीक्षक महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा डाँक्टर अरुण गौड़ थे।

लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर ने बताया कि समारौह की अध्यक्षता कर रही मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्या डाँक्टर वर्षा सिंह ने अपने उद्धबोधन में उनके स्वयं के लैब कार्य के अनुभव के आधार पर बताया कि लैब टेक्नीशियन के बिना लैब के संचालन का कार्य संभव नहीं हो सकता, इसलिए लैब टेक्नीशियन लैब के साथ ही साथ चिकित्सा जगत के भी मजबूत स्तंभ होते हैं।

बाद इसके समारौह के बतौर मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए चिकित्सा अधीक्षक डाँक्टर अरुण गौड ने कहा की कोरोना कॉल के समय में लैब टेक्नीशियन ने अपनी जान जौखिम में डालकर कोरोना रोगियों के सैंपल लेकर उनकी जाँच करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लैब टेक्नीशियन के इसी सहयोग के चलते पूरे भारत वर्ष में भीलवाड़ा कोरोना कॉल में रोल मॉडल बन पाया था।

जिलाध्यक्ष लैब टेक्नीशियन तँवर ने प्रयोगशाला सहायक के अध्यक्ष रामपाल भांड की मौजूदगी में बोलते हुए लैब कार्य को चिकित्सा विभाग की रीड की हड्डी बताते हुए बताया कि रोगी के रोग का निदान करने में लैब टेक्नीशियन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। जिसके द्वारा की गई जाँच के बाद ही एक चिकित्सक रोगी का सफलतापूर्वक इलाज कर पाता हैं। इसके साथ ही साथ अपराधियों को सजा दिलाने में भी फॉरेंसिक लैब में सैंपल जांच के कार्यो को करने में भी लैब टेक्नीशियन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन भी करते हैं।

अखिल राजस्थान लेबोरेट्री टेक्नीशियन कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा के कोषाध्यक्ष एवं महात्मा गाँधी अस्पताल भीलवाड़ा के ब्लड बैंक प्रभारी दिनेश चन्द्र शर्मा ने लैब टेक्नीशियन दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जैनसेन मिडिलबर्ग हॉलैंड में हंस जानसेन नामक एक चश्मा निर्माता का बेटा था। साथ ही जकारियास को यौगिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया जाता हैं।

ब्लड बैंक प्रभारी शर्मा ने बताया की यौगिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का हंस जानसेन के बेटे जकारियास जानसेन और हंस लिपरशी ने 1590 के आसपास मिश्रित सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने का श्रेय प्राप्त हुआ था। हंस और जकारियास जानसेन जो की डच में चश्मा निर्माता थे। उन्होंने एक ट्यूब के अंत में अलग-अलग शक्ति के दो लेंस रखकर पहला सरल माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। वे ट्यूब के माध्यम से सूक्ष्म कणों के विस्तार का निरीक्षण भी किया करते थे।

इस समारोह का संचालन उप नर्सिंग अधीक्षक मुकुट राज सिंह शक्तावत ने किया।

इस समारोह में नर्सिंग अधीक्षक कैलाश शर्मा, रेडियोग्राफर प्रभारी घनश्याम असावा, नर्सेज संगठन के पदाधिकारी लकी ब्यावट, फरीद मोहम्मद रंगरेज, लैब टेक्नीशियन संघ के हरि बल्लभ शर्मा, कृष्ण गोपाल सर्वा, दिनेश चंद्र शर्मा, गोपाल डीडवानिया, शोभाराम रेगर, आत्माराम धाकड़, भागचंद सोनी, हिना धवल, अरविंद सनाढ्य व कपिल जोशी आदि उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023